PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 248 ● भिलाई, शनिवार 11 अप्रैल 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए एक बार फिर दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. सचिवालय की कई आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश आने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया. दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट मोड पर हैं और जांच में जुटी हैं. आज दिल्ली सचिवालय की विभिन्न ईमेल आईडी पर एक साथ धमकी भरे मेल प्राप्त हुए. संदेश में सचिवालय परिसर को बम से उड़ाने का दावा किया गया था. जैसे ही इस सूचना की पुष्टि हुई, तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया. मौके पर दिल्ली पुलिस की बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वायड की टीमें पहुंचीं. इसके बाद पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई. सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय के चप्पे-चप्पे की जांच की गई है. हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. लेकिन पुलिस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है. ऐसे में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल अब उन ईमेल आईडी की बारीकी से जांच कर रही है, जिनसे यह संदेश भेजे गए थे. आईपी एड्रेस व सेंडर की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश.

जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह के बयान दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया. गवाह निधि भारद्वाज के बयान दर्ज किए गए. आरोपी जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने निधि भारद्वाज का क्रास-एग्जामिनेशन किया. कोर्ट में गवाह मनमोहन कौर का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया. उसके बाद कोर्ट ने मनमोहन कौर का नाम गवाहों की सूची से हटाने का आदेश दिया.

वृंदावन में मातम

यमुना नदी में नाव पलटने से पंजाब के 10 पर्यटकों की मौत

मथुरा / एजेंसी

मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. दोपहर 2:45 बजे के करीब श्रीबांके बिहार मंदिर से करीब ढाई किमी की दूरी पर स्थित केशी घाट के पास पर्यटकों से भरी एक नाव (मोटर बोट) पोंटून पुल (पीपा पुल) से टकराने के बाद यमुना नदी में पलट गई. नाव में 30 से अधिक लोग सवार थे, जो नदी में गिर गए. इनमें से 10 लोगों की डूबकर मौत हो गई, जबकि 22 को बचा लिया गया. अब भी कुछ लोग नदी में लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है. मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि नाम में सवार लोग पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं. स्थानीय गोताखोर गुलाब ने इस हादसे के लिए तेज हवा को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आजतक से बातचीत में कहा, 'तेज हवा चल रही थी. यमुना नदी के बीच में नाव अचानक तेज हवा से डगमगाने लगी और उसकी स्पीड भी बढ़ गई. देखते ही देखते नाव पीपा पुल (पांटून पुल) से टकराकर नदी में पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गहरे पानी में गिर गए.' मथुरा जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, स्थानीय पुलिस करीब और 50 स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही हैं. मथुरा के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि दुर्घटना का प्रारंभिक कारण यह प्रतीत होता है कि

नाव पोंटून पुल से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ. उन्होंने बताया कि घटनास्थल से दस शव बरामद किए गए हैं. एनडीआरएफ एसडीआरएफ फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें, स्थानीय गोताखोरों और नाविकों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं. लापता लोगों की तलाश जारी है. मथुरा ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि केशी घाट के पास यमुना नदी के एक हिस्से में नाव डूब गई है. अब तक 22 लोगों को नदी से बाहर निकाला जा चुका है. उन्होंने कहा, 'बचाए गए लोगों को एम्बुलेंस और पुलिस वाहन (पीआरवी) की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. हम फिलहाल स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि पता चल सके कि कितने लोग सुरक्षित हैं और कितने लोगों की जान गई है... यहां एक पोंटून पुल है. चूंकि यह पुल जर्जर हालत में था, इसलिए एक एजेंसी पोंटूनों की मरम्मत का काम कर रही थी. आशंका है कि यह दुर्घटना इसी मरम्मत कार्य के दौरान नाव के पोंटून से टकराकर पलटने के कारण हुई. मथुरा के जिलाधिकारी सीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालुओं को ले जा रही एक नाव यमुना नदी में पलट गई, जिससे एक दुखद हादसा हो गया।

दिल को झकझोर देने वाली है ये घटना : सीएम योगी

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि जनपद मथुरा में नाव पलटने से हुई मौतें बेहद दुखद और दिल को झकझोर देने वाली हैं. उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने और घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हादसा दोपहर पौने 3 बजे केशी घाट पर हुआ, जो श्रीबांके बिहार मंदिर से करीब ढाई किमी की दूरी पर है. नाव पीपा पुल से टकराने के बाद नदी में पलट गई. स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें करीब 50 स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है.

चुनावी रैली में भाजपा पर बरसीं सीएम ममता

सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है,लेकिन उनपर नहीं..

कोलकाता/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर तीखा हमला किया। उत्तर 24 परगना जिले के टेंटुलिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को असम के स्थानीय लोगों के वोटों पर भरोसा नहीं था। इसलिए पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए बाहर से लोग बुलाए। ममता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को ट्रेन में भरकर असम लाया गया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में देश की कोई भी एजेंसी निष्पक्ष नहीं रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केसरिया पार्टी ने सभी एजेंसियों को खरीद लिया है। भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, 'एक सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं।' पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख नाम हटा दिए गए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इन 90 लाख नामों में से 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम हैं। उन्होंने असम के एनआरसी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 19 लाख नाम लिस्ट से बाहर किए गए थे, जिनमें 13 लाख हिंदू और 6 लाख मुस्लिम थे। ममता बनर्जी ने लोगों को आगाह किया कि वे भाजपा पर कभी विश्वास न करें।

मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल के अंदर लगी आग, दमकल टीम मौके पर पहुंची

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आग लगने की खबर है। खबरों के मुताबिक, हवाई अड्डे के टर्मिनल वन पर मौजूद बैठक क्षेत्र में आग लगी है। ये घटना शाम 6 बजे के करीब की बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, आग हवाई अड्डे परिसर में विले पार्ले (पूर्व) स्थित 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। मुंबई अग्निशमन दल के प्रमुख रविंद्र अंबुलगेकर का कहना है कि आग टर्मिनल के अंदर केबल ट्रे और स्विच बॉक्स में लगी थी।

उच्च सदन से शुरू की नई पारी

नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ....

नई दिल्ली/ एजेंसी

बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज राज्यसभा से अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। आज दोपहर 12:12 बजे उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इसके लिए समारोह का आयोजन किया गया। राज्यसभा में सारी तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर राज्यसभा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके आवास से उनके साथ राज्यसभा पहुंचे। 16 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद् सदस्य के रूप में इस्तीफा दिया। इसके बाद आज उन्होंने राज्यसभा सांदस के रूप में शपथ लिया। अब तीन से चार दिनों के अंदर वह अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। एक दिन पहले यानी नौ अप्रैल को दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब हम यहीं रहेंगे, वहां नए लोगों को मौका मिलेगा। बहुत समय तक यहां (दिल्ली) काम किया है, अब फिर से यहीं काम करूंगा। 20 साल तक बिहार में बहुत काम किया है। यह काम आगे भी काम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा में शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलकात करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखी विधायकी

जेल में बंद अब्बास अंसारी को बड़ी राहत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हेट स्पीच से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सजा पर रोक वाले फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता बनी रहेगी और फिलहाल उस पर कोई खतरा नहीं है।दरअसल, हेट स्पीच से जुड़े एक केस से में निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता फिलहाल बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सरकार द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया जाए।

नासिक की आईटी कंपनी में 8 महिलाओं से यौन शोषण, 6 गिरफ्तार

नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी में महिला कर्मचारियों के यौन शोषण से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि कंपनी की महिला कर्मचारियों की शिकायतों के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें टीम लीडर और इंजीनियर स्तर के कर्मचारी शामिल हैं। सभी पर अलग-अलग आरोप हैं। वहीं, पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) भी गठित की गई है। पुलिस ने बताया कि 9 पीड़ितों की शिकायत के बाद मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पीड़ितों में 8 महिलाएं और एक पुरुष है। 8 एफआईआर मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में और एक देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है।

वकील ने दायर की अलग-अलग 25 जनहित याचिकाएं

पहले भी कर चुके थे अटपटी मांग;पहले भी खा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से फटकार...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 25 अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर करने वाले वकील को सलाह दी कि उन्हें अदालत में आने के बजाय संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, याचिकाकर्ता और वकील सचिन गुप्ता ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि वह अपनी पीआईएल वापस लेना चाहते हैं। पीठ ने गुप्ता से कहा, आप अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अदालतों में आने के बजाय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए, उन्हें कुछ मुद्दों पर अधिक जानकारी देनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उचित समय आने पर अगर जरूरत हुई तो न्यायालय उनकी याचिकाओं पर भी विचार करेगा। सीजेआई सूर्यकांत ने जोर दिया कि एक वकील और कानूनी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के रूप में याचिकाकर्ता को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से मुद्दों की पहचान करनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता अदालत का रुख कर सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई 25 पीआईएल वापस लेने की अनुमति दे दी।

याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई पीआईएल में देश में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक सामान्य संपर्क भाषा विकसित करने हेतु नीति बनाने और आम जनता के बीच कानूनी ज्ञान फैलाने के लिए टेलीविजन पर कानूनी जागरूकता शो हेतु नीति का मसौदा तैयार करने सहित विभिन्न दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। पीआईएल में साबुन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने और केवल उन्हीं रसायनों की अनुमति देने के लिए नीति बनाने की दिशा में निर्देश शामिल थे जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारते हैं।

बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र

अमित शाह बोले-45 दिन के अंदर 7 वां वेतन आयोग लागू करेंगे और यूसीसी भी लागू होगा

कोलकाता/ एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे में है। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे 'भरोसे का पत्र' बताया। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा के माहौल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। अमित शाह के अनुसार, इस घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से जूझ रहे किसानों को इससे नई दिशा मिलेगी, जबकि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी इसमें

प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा अमित शाह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर ही सातवें वेतन आयोग और आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही छह माह के अंदर ही यूसीसी भी लागू करेंगे। महिलाओं के लिए एलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार 'लक्ष्मी भंडार' योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक खाते में 3 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मंडल में महिला थाने और महिला डेस्क स्थापित करने की योजना है, ताकि महिलाओं को बेहतर और त्वरित सहायता मिल सके। यह भी कहा गया है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल न उठे और उन्हें किसी भी समय बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस न हो। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने की योजना है।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को 7 दिनों की मोहलत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें खेड़ा पर मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप है। इस फैसले से फिलहाल खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिससे ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है लेकिन पवन खेड़ा को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वह अब भी अपनी राजनीतिक बयानबाजी इसी अंदाज में जारी रखेंगे या नहीं।

नगरी, सिहावा क्षेत्र के सत्तापक्ष से जुड़े जुआ किंग पर पुलिस विभाग मेहरबान

धमतरी। पिछले दिनों पुलिस विभाग द्वारा सट्टा, जुआ पर अंकुश लगाने जाने को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें विभाग प्रमुख ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे अपराधों पर सख्ती के साथ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया में अक्सर देखा गया है कि छोटे-मोटे जुआ खेलने वाले लोगों पर ही पुलिस विभाग कार्यवाही कर अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का पालन करते हैं जबकि वास्तविकता यह है कि सत्तापक्ष से जुड़े एक जुआ किंग पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी मेहरबान हैं, तभी तो इस पर आज तक किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। सिहावा नगरी स्थित रहने वाले इस किंग की जानकारी सभी को है, लेकिन सत्तापक्ष से जुड़े रहने के कारण इस पर अब तक कार्यवाही नहीं हो पाई है। विभाग के कुछ लोगों की मानें तो क्षेत्र के सट्टा किंग को विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, यही कारण है कि उक्त किंग यह कहते फिरता है कि मेरी ऊपर से सीधे सेटिंग है, इसलिये छोटा अधिकारी मेरे गिरेबान पर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकता। हर माह मेरे द्वारा इस अनैतिक कार्य को करने के एवज में भेंट पूजा पहुंचाई जाती है। जिले में जुआ, सट्टा, अवैध शराब, चाकूबाजी, सूखा नशा, अड्डेबाजी जैसे अनेक अपराध हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं तब उजागर होती है जब कोई वारदात हो या पकड़ में आता हो। लेकिन पुलिस विभाग स्वयं से ऐसे स्थलों में दबिश भी नहीं देता जिसके कारण उपरोक्त गैर कानूनी कार्य शहर के भीतरी ईलाकों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी घटित होते आ रहे हैं। विभाग द्वारा सायबर सेल, अजाक शाखा, शक्ति टीम, पेट्रोलिंग वाहन, हाईवे पेट्रोलिंग, आईटी सेल के नाम पर अनेक वाहनें शहर के मुख्य मार्गों में दौड़ती दिखाई देती हैं। लेकिन शहर के बाहर क्षेत्रों में ऐसी वाहनें कभी भी गश्त नहीं करती और इसी का लाभ लेकर अड्डेबाजी करने वाले लोग ऐसे शख्स की तलाश में रहते हैं जिससे वे अवैध वसूली करें, न देने पर चाकूबाजी करें। ऐसे लोग शराब का सेवन कर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जो अपने साथ घटित घटना की सूचना या रिपोर्ट पुलिस को नहीं देते और वे अपने गंतव्य को निकल जाते हैं। पुलिस विभाग के द्वारा लगातार अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये समय समय पर बैठकें आयोजित की जाती है परंतु इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। सिर्फ विज्ञप्ति आती है और इस विज्ञप्ति में अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। अवैध शराब पकड़ा जाता है और लंबी चौड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है ताकि लोगों को पढ़ने से यह पता चले कि पुलिस विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है जबकि वास्तविकता कुछ और ही रहती है। विभाग द्वारा पिछले लंबे समय से छोटे अपराधों को पकड़कर बकायदा उसकी जानकारी मीडिया को दी जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो राजिम से आकर सट्टा खिलायें, जुआ फड़ संचालित करें, ऐसे रसूखदार लोगों पर पुलिस विभाग पूरी तरह मेहरबान नजर आता है। तभी तो ऐसे लोग आज तक कानून के शिकंजे में नहीं लाये गये हैं। सिहावा, नगरी क्षेत्र में सत्तापक्ष से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा विभाग के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को मैनेज कर लंबे समय से जुआ खिलवाया जा रहा है। इसकी खबर पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों को है। लेकिन उक्त जुआ किंग सत्तापक्ष से जुड़े रहने के कारण अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आया है जिसके पीछे अधिकारियों की मिलीभगत बताई जा रही है। जिले के जागरूक नागरिकों ने दिखावे की कार्यवाही को बदलते हुए ऐसे बड़े रसूखदार जुआ, सट्टा किंग को पकड़ने के पश्चात ही लंबी चौड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की बात कही, और कहा गया कि तब समझ आयेगा कि पुलिस निष्पक्षता के साथ कार्यवाही कर रहा है। जुआ किंग द्वारा चलाये जा रहे अभियान के चलते अनेक व्यक्ति कंगाल हो चुके हैं जो अपना जमीन-जायदाद बेचकर यहां तक घर के बरतन बेचकर भी इस अवैध कृत्य के चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन पुलिस है कि उक्त जुआ किंग को पकड़ने का साहस ही नहीं करती। खबर के मुताबिक यह भी पता चला है कि उसका नेटवर्क सिहावा, नगरी के साथ साथ धमतरी, कुरूद, में भी धड़ल्ले से चल रहा है।

विश्व नवकार मंत्र दिवस पर स्थानक भवन में भव्य आयोजन

धमतरी। विश्व नवकार मंत्र दिवस के अवसर पर विश्व में एक साथ नवकार मंत्र का जाप किया गया। सुबह लगभग 8.10 बजे से 9.36 बजे तक विश्वभर में जैन धर्मावलंबियों ने इस महामंत्र का स्मरण कर विश्व शांति, मानव कल्याण और आत्मिक उन्नति की कामना की। इसी क्रम में धमतरी शहर के सिहावा चौक स्थित जैन स्थानक भवन में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन में जैन समाज के महिला, पुरुष, युवा और बच्चों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने एक साथ एक स्वर में नवकार मंत्र का जाप किया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया। कार्यक्रम स्थल पर अनुशासन, शांति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। समाज के वरिष्ठजनों व पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि नवकार मंत्र जैन धर्म का मूल और सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो किसी विशेष व्यक्ति या देवता का नहीं बल्कि पंच परमेष्ठी, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की वंदना का प्रतीक है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है तथा जीवन में सुख,शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने आगे कहा कि नवकार मंत्र केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह समता, अहिंसा, विनम्रता और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला सार्वभौमिक मंत्र है। आज के दौर में, जब समाज में तनाव और अशांति बढ़ रही है, ऐसे में इस प्रकार के सामूहिक जाप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और युवाओं में भी खास उत्साह देखने को मिला, जो जैन संस्कृति और परंपरा के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। महिलाओं की भी बढ़ी भागीदारी रही, जिन्होंने पूरे आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में सभी श्रद्धालुओं ने विश्व में शांति, सद्भावना और समृद्धि की कामना करते हुए नवकार मंत्र के महत्व को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती दी, बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी प्रसारित किया।

जिला स्तरीय बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता 12 अप्रैल से

धमतरी। जिले के युवाओं को खेल के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करने और नए खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 12 अप्रैल 2026 से स्थानीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गंगरेल में आयोजित होगी। इसके लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता ओपन कैटेगरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें आयु की कोई बाध्यता नहीं होगी। प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में आयोजित की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। जिले में पहली बार इस प्रकार की बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को नई खेल गतिविधियों से जोड़ना और उनके कौशल का विकास करना है। इच्छुक प्रतिभागी अपना पंजीयन विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुरूद, मगरलोड, नगरी या जिला खेल कार्यालय, धमतरी में करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए खिलाड़ी सहायक खेल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने अधिक से अधिक युवाओं से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है, ताकि खेल भावना को बढ़ावा मिल सके और जिले की खेल प्रतिभाओं को नया मंच प्राप्त हो।

समाज में खेलों के प्रति जन जागरूकता लाने का सबसे सार्थक माध्यम है मातृशक्ति: पं.राजेश शर्मा

धमतरी। शहर के प्रत्येक वर्ग के लोगों को विभिन्न खेल गतिविधियों से जोड़कर स्वस्थ, सक्षम एवं मजबूत पीढ़ी समाज को समर्पित करने की दृष्टिकोण से धर्म प्रेमी समाज से भी पंडित राजेश शर्मा द्वारा पहल करते हुए महीने भर अनेक खेलों का आयोजन किए जाने की श्रृंखला चालू है जिसमें रात्रि कालीन टेनिस बॉल क्रिकेट के बाद मिशन मैदान में महिलाओं के लिए विभिन्न स्पर्धाओं जिसमें नींबू-चम्मच दौड़, मटकी फोड़, कुर्सी दौड़, फुगड़ी, बिल्लस, रस्सी दौड़ के आयोजन में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया गया जिसमें अनेक पुरस्कार रखे गए थे। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंचकर अपना दमखम दिखाने के लिए आतुर रही। महिला खेलकूद के समापन अवसर पर आयोजक पंडित राजेश शर्मा ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों के प्रति जागरूकता लाने के

लिए सबसे सार्थक माध्यम मातृशक्ति है जिनके द्वारा ही समग्र समाज के लिए मजबूत युवाओं की फौज तैयार करके स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए एक कड़ी के रूप में यहां खेल पखवाड़ा साबित होगा इसके लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। उक्त आयोजन में खेल पखवाड़ा के मुख्य सलाहकार हेमलता शर्मा, पार्वती वाघवानी, चंद्रकला पटेल, प्राची सोनी, सरिता यादव, नम्रता पवार, ईश्वरी पटवा, दमयंती गजेंद्र, रेखा शांडिल्य, ममता सिन्हा, प्राती वासानी, गायत्री सोनी, हर्ष महेश्वरी, बरखा शर्मा, झरना दादर, गोमती रजक, राखी रायचूर, सुशीला तिवारी, हिमानी साहू, भारती साहू, देवपति देवांगन, जानकी पटेल, पद्मिनी पटेल, ममता पटेल, जागृति पटेल, रेशमा शेख, विमल पटेल, श्याम पटेल, राजकुमारी पटेल, सीमा पटेल, लोमेश साहू, भावना सोनी, रानी सोनी, डाली सोनी, भावना यादव, शशि साहू, परमेश्वरी साहू, डॉली शर्मा, आभा वैष्णव, गीता शर्मा, संतोषी साहू, चित्रलेखा निर्मलकर, सरोज नामदेव, कंचन तारा, कनक शाह, हरमीत कौर, रितिक यादव, कुलदीप कौर, गायत्री साहू, शांत साहू, हेमा दुबे, पूर्णिमा साहू, लक्ष्मी सोनी, चेतना रणसिंह, दीपेश साहू, ईश्वरी पटवा, रेखा रजक, पायल यादव, भाग्यश्री गजेंद्र, अखिलेश सोनकर, कुलेश सोनी, पिंटू यादव, नीलमणि पावरिया, राजकुमार लॉटरी, मुकेश शर्मा, विकास शर्मा, जीतू यादव, पन्ना साहू, देवेंद्र साहू, कोमल सार्वा, योगेश रायचुरा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम का संचालन प्राची सोनी तथा हर्षा महेश्वरी द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन हेमलता शर्मा ने किया।

अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में प्रतिभा स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

सरायपाली। प्रतिभा स्कूल में सत्र 2025-26 के अंतर्गत विज्ञान ओलंपियाड फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के प्रथम स्तर में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। प्रतियोगिता में कक्षा 1 से अनंत अग्रवाल, काशवी अग्रवाल, नित्या अग्रवाल एवं श्रीजा पाणिग्रही, कक्षा 2 से ओनोर अग्रवाल, समर्थ अग्रवाल एवं सात्विक अग्रवाल, कक्षा 3 से अनवी अग्रवाल, कक्षा 4 से मिमांसा नायक तथा कक्षा 5 से अर्श अग्रवाल ने कक्षा टॉपर बनकर गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया। विद्यालय की प्रार्थना सभा में इन सभी मेधावी विद्यार्थियों को प्राचार्य नरहरि पटनायक द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संचालक डॉ. आभाष अग्रवाल, उप प्राचार्य नासिर खान एवं समस्त शिक्षक परिवार ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय के ओलंपियाड शाला समन्वयक नीलम पाणिग्राही के अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन से पिछले 8 वर्षों से प्रतिभा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी विज्ञान ओलंपियाड में निरंतर सफलता के नए माप दंड हासिल किए हैं।

रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, महापौर ने दिखाया हरी झंडी

धमतरी। प्रभु रामलला के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं का एक विशेष जत्था बड़े उत्साह, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुआ। जनपद कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिक निगम धमतरी के महापौर रामू रोहरा एवं जनपद अध्यक्ष मती अंगिरा ध्रुव मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया और सभी को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर महापौर रामू रोहरा ने अपने विस्तृत उद्बोधन में कहा कि प्रभु राम केवल एक आस्था नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और मर्यादा के

सर्वोच्च आदर्श हैं। उनका जीवन हमें सत्य, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और अनुशासन का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद देशभर में श्रद्धालुओं के मन में अपार उत्साह है और हर कोई प्रभु के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। महापौर ने आगे कहा कि इस प्रकार की धार्मिक यात्राएं व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और समाज में भाईचारा, एकता एवं सद्भाव को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे यात्रा के दौरान संयम, अनुशासन एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, ताकि यह यात्रा सभी के लिए सुखद अनुभव बन सके। रोहरा ने यह भी कहा कि नगर निगम सदैव श्रद्धालुओं की सुविधा और सहयोग के लिए तत्पर है तथा भविष्य में भी ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित करता रहेगा। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियोंए नागरिकों एवं श्रद्धालुओं ने प्रभु राम के जयघोष के साथ जत्थे को विदाई दी।

रुद्री बैराज में डूबने से युवक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

धमतरी। धमतरी जिले के रुद्री बैराज में नहाने गए युवकों के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज पानी के बहाव में एक युवक डूब गया, जिसे उसके साथियों ने तत्काल बाहर निकाल लिया।

मिली जानकारी के अनुसार रुद्री बरॉज में नहाने गये एक युवक की पानी के तेज बहाव में डुब गया जिसे तुरंत ई.रिक्शा के माध्यम से धमतरी के श्री राम हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी रहा। करीब 4 से 6 घंटे तक चले उपचार के बाद युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान विशाल कोसरे उम्र 21 वर्ष, निवासी जोधपुर के रूप में हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जाती रही है कि तेज बहाव वाले स्थानों पर नहाने से बचें। इसके बावजूद ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं।

भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ी

अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026

गरियाबंद। भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 10 अप्रैल 2026 कर दी गई है। पहले यह तिथि 13 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक निर्धारित थी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वॉइन इंडियन आर्मी डॉट इन के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। जिले के अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार जिनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं एवं 10वीं) के पदों के लिए पात्र हैं। सिपाही पद के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जुलाई से अगस्त 2026 के बीच में आयोजित होने की संभावना है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 0771-2965214 या जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबंद के दूरभाष क्रमांक 07706-241269 पर संपर्क किया जा सकता है।

बस्तर में विकास नहीं विनाश की बन रही रणनीति, विरोध को दबाने नहीं हटाया जा रहा बल

महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव छ.ग. शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने भाजपा की साय सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को 100 फीसदी नक्सल मुक्त होने की बात कही है। चंद्राकर ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से लाल आतंक मुक्त हो चुका है तो अतिरिक्त 60 हजार सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी बस्तर क्षेत्र में क्यों है। इन 60 हजार सुरक्षा बलों में 40 हजार केंद्रीय रिजर्व फोर्स है। जिन्हें अब वापस भेज देना चाहिए। लेकिन, सरकार एक साल तक और फोर्स की तैनाती बस्तर में करने की बात कह रही है। इसका अर्थ है कि या तो अभी भी छत्तीसगढ़ पूरी तरह नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, या फिर हसदेव की तरह अबूझमाड़ के जल, जंगल जमीन को भी अडाणी को सौंपने की योजना भाजपा द्वारा बनाई जा रही है। ताकि, विरोध होने पर आसानी से फोर्स की मदद से उन्हें नियंत्रित की जा सके। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की समाप्ति से अबूझमाड़ के विकास में तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होकर शांति का टापू बने यह सभी चाहते हैं। लेकिन, विकास के नाम पर विनाश की जो रणनीति भाजपा बना रही है, वह प्रदेश के वनवासियों के साथ छल है। क्योंकि, 60 हजार बल की तैनाती अभी भी बस्तर में है। सरकार का तर्क है कि स्थिति सामान्य होने तक तथा विकास कार्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बल की नियुक्ति की गई है। अब सवाल यह उठता है कि गृहमंत्री अमित शाह के डेडलाइन अनुसार जब 31 मार्च 2026 तक प्रदेश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसे में बस्तर के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि, वनांचल क्षेत्र के भोलेभाले आदिवासी भला विकास कार्यों में क्या अवरोध उत्पन्न करेंगे। विरोध तब होगा जब आदिवासियों से उनका जल, जंगल, जमीन छीना जाएगा। क्योंकि, पहले ही भाजपा की साय सरकार ने अडानी के लिए हसदेव अरण्य के लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हरे-भरे जंगल को काटकर आदिवासियों की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पूर्व संसदीय सचिव ने कहा कि हसदेव अरण्य देवभूमि से जहां आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता जुड़ी है। यही नहीं, जिस दंडकारण्य में प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल के सबसे अधिक समय बीताए थे, उसे भी भाजपा की सरकार ने अडानी प्रेम का भेंट चढ़ा दिया। अब अबूझमाड़ के शेष वनांचल क्षेत्र को पुनः अडाणी के नाम पर बलि देने की योजना भाजपा बना रही है।

राधा-कृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निकली भव्य कलश यात्रा ,उमडी श्रद्धालुओं की भीड़

सरायपाली। भव्य राधाकृष्ण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव ग्राम केना के प्रथम दिवस मंदिर परिसर से गाँव की गलियों से होते हुए दर्री तालाब तक बाजे-गाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पीत वस्त्र धारी हजारों महिलाओं के साथ युवतियों ने भी कलश उठाया। यात्रा के दौरान श्रध्दालुओं द्वारा लगाए लगाए जा रहे राधे-कृष्ण की जयकारे से पुरा वातावरण कृष्णमय हो गया। दुर-सुदुर तथा विभिन्न पंचायतों से आई हुई महिलाएँ हुलहुली और जयकारे के साथ चल रही थी। जिस रास्ते से कलश यात्रा गुजर रही थी वह लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। कलश यात्रा दर्री तालाब पहुँची और वहाँ से मंत्र से अभिसिंचित जल कलश में भरा गया। विद्वतजनों ने मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापना की गई। इस अवसर पर मुख्य यजमान सुन्दर लाल पटेल ग्राम गौटिया, मंदिर अध्यक्ष, टिकेश्वर साहू, उपाध्यक्ष नरोत्तम भोई, रामरतन पटेल,, विजय चौधरी, टिकेश्वर पटेल, तिरिथलाल पटेल ने सम्पूर्ण धार्मिक कार्यक्रम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से सम्पन्न कराया। कुल पुरोहित पंडित खिरोद्र कर, पंडित विद्याधर दास, यज्ञाचार्य पं. त्रिलोचन कर, जोगेंद्र दास, अजय दास, सुभाष मिश्रा, ब्रह्मप्रकाश कर ने विधिवत वैदिक रीति-नीति के अनुसार पूजन करवाया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन वंदेमातरम् सेवा संस्थान छ.ग. के उपाध्यक्ष जन्मजय नायक कर रहे हैं। दिव्य प्रेम, सर्वोच्च भक्ति और ईश्वर के साथ आत्मा के मिलन का प्रतीक यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाभंडारे के साथ निरंतर आगामी पाँच दिनो तक चलेगा।

संक्षिप्त समाचार

4 करोड़ रूपए की ठगी, मध्य प्रदेश से तांत्रिक गिरफ्तार

रायपुर। चटिया-मटिया और तंत्र-मंत्र के सहारे शेयर ट्रेडिंग के नाम पर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लगभग 4 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने इंदौर मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मिलन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार कोमल साहू ने 17 अक्टूबर 2025 को मानसिक तनाव के चलते जहर सेवन कर लिया था, जिसको उपचार के दौरान मौत हो गई। मर्ग जांच के दौरान मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ तथा बैंक स्टेटमेंट व मोबाईल डेटा की गहन जांच की गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी मोहम्मद अजीज खान ने मृतक को शेयर मार्केट में निवेश और तंत्र-मंत्र चटिया-मटिया के माध्यम से रकम दोगुना करने का लालच देकर लगभग 4 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी की थी। रकम वापस न मिलने और कर्जदाताओं के दबाव के चलते कारण कोमल साहू अत्यधिक मानसिक तनाव में था, जिसके उसने आत्महत्या कर ली। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को घेराबंदी कर उसे इंदौर मध्यप्रदेश से गत 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नगद और बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों की राशि प्राप्त करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफधारा 318-4, 108, 3-5 बीएनएस कायम कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई: दुर्ग की डिस्टलरी से 3 वाहन जब्त, अवैध परिवहन का खुलासा

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शराब घोटाले की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग स्थित डिस्टलरी से तीन वाहनों को जब्त किया है। जांच में सामने आया है कि इन वाहनों का इस्तेमाल अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। प्राथमिक जांच में डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह पुष्टि हुई है कि इन वाहनों के जरिए डिस्टलरी से सीधे कुछ चयनित शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी। इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने के लिए डिस्टलरी संचालक अपने विश्वसनीय लोगों के माध्यम से छोटे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों का उपयोग कर रहा था। यह कार्रवाई शराब घोटाला प्रकरण क्रमांक 04/2024 के तहत की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जांच जारी है। इससे पहले भी बिलासपुर और मुंगेली जिले की डिस्टलरियों से कुल 16 वाहनों को जब्त किया जा चुका है। जांच एजेंसी के अनुसार, अवैध शराब परिवहन के लिए कुछ विशेष वाहनों का बार-बार उपयोग किया जाता था, जिन्हें साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चिन्हित किया गया। वहीं, जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ अन्य वाहनों का इस्तेमाल करने के बाद में उन्हें स्क्रैप कर दिया गया या अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है।

अगले दो दिनों तक नहीं मिलेगी राहत, कभी बारिश तो कही तेज हवाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बुधवार को भी कई जिलों में बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में बने नए सिस्टम के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिनों के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। दो दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना है। हल्की और मध्यम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकता है। वहीं, इस दौरान तेज हवाएं लगने की भी संभावना है। राज्य का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बंगाल में बने तूफानइन का असर छत्तीसगढ़ में देखने का मिल रहा है। जिस कारण से अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन राज्य के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों तक राज्य में 40 से 50 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव जिले का दर्ज किया गया है। जिले में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण गिरावट दर्ज हुई है। वहीं, राज्य में सबसे न्यूनतम तापमान अंबिकापुर जिले का दर्ज किया गया है। अंबिकापुर जिले का तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर में मौसम सामान्य बना हुआ है। लोगों को गर्मी से हल्की राहत है। रायपुर में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। रायपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

शराब घोटाले में सियासी संग्राम तेज, सौम्या चौरसिया समेत 3 पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा, 51 आरोपी फंसे जाल में

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में जांच ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया है जहां आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 8 अप्रैल 2026 को विशेष न्यायालय में नया पूरक चालान पेश कर दिया है और इस बार कार्रवाई सीधे सत्ता, सिस्टम और सिंडिकेट के गठजोड़ तक पहुंचती दिख रही है, इस पूरक चालान में तीन गिरफ्तार आरोपी– तत्कालीन उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना—को मुख्य रूप से आरोपित किया गया है, जांच में सामने आया कि देवेन्द्र डडसेना जो राजीव भवन का पुराना एकाउंटेंट रहा है उसने अवैध शराब सिंडिकेट से जुटाई गई रकम को प्राप्त करने, सुरक्षित रखने और निर्देशानुसार आगे भेजने का काम किया जिससे वह इस पूरे आर्थिक अपराध की चेन का अहम हिस्सा बन गया, वहीं के.के. श्रीवास्तव की भूमिका सिर्फ परिवहन तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने अवैध नगद राशि के उठाव, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, उसके प्रबंधन, निवेश और खपाने तक में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस नेटवर्क को मजबूत किया, जांच एजेंसी के अनुसार सौम्या चौरसिया ने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए इस सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय और प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराई जिससे यह पूरा खेल लंबे समय तक चलता रहा और शासन के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा।

छत्तीसगढ़ में एआई आधारित शिक्षा की नई शुरुआत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से गूगल इंडिया प्रतिनिधियों की मुलाकात

- एआई आधारित शिक्षा से छत्तीसगढ़ को ज्ञान, कौशल और नवाचार का अग्रणी केंद्र बनाना हमारा ध्येय है: मुख्यमंत्री
- रायपुर से शुरू होगा एआई सक्षम शिक्षा अभियान', छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक शिक्षकों को मिलेगा एआई प्रशिक्षण

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन एवं गूगल इंडिया के पब्लिक पॉलिसी प्रमुख श्री राजेश रंजन ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान करते हुए उन्हें शॉल एवं बस्तर कला की प्रतिकृति भेंट की। । गूगल फॉर एजुकेशन इंडिया के प्रमुख श्री संजय जैन ने रायपुर जिला प्रशासन और गूगल के मध्य हुए लेटर ऑफ इंटेंट की जानकारी साझा करते हुए बताया कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्षम शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सक्षम शिक्षक अभियान के तहत राज्य में शिक्षकों को आधुनिक डिजिटल टूल्स और AI आधारित शिक्षण

पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल के प्रथम चरण की शुरुआत रायपुर से की जाएगी, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तार दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2 लाख से अधिक शिक्षकों को AI प्रमाणन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए गूगल फॉर एजुकेशन अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है, जिससे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा सके। कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में 200 शिक्षकों की सहभागिता से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, कक्षा शिक्षण में AI के प्रभावी उपयोग और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक-सक्षम और नवाचार आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शिक्षा से जोड़ना केवल एक पहल नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल शिक्षण पद्धतियों में गुणवत्ता आएगी, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर नए युग के कौशल विकसित होंगे, जो उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सक्षम शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने गाँव चलो-घर चलो अभियान की शुरुआत...

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मंगलवार को जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के नानगुर मण्डल के ग्राम जामावाड़ा में पहुँचकर 'गाँव चलो-घर चलो' अभियान की शुरुआत की? और जामावाड़ा की ग्रामीण जनता से सीधा सम्वाद करते हुए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए चर्चा की। श्री देव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, यह भाजपा सरकार की मंशा है। 'गाँव चलो-घर चलो' अभियान का यही उद्देश्य भी है। विदित रहे, अपने 47वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा 7 से 12 अप्रैल तक सघन जनसम्पर्क करने 'गाँव चलो-घर चलो' अभियान चला रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने 'गाँव चलो-घर चलो' अभियान में ग्राम जामावाड़ा में 19 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण का भूमिपूजन किया। कासरीपारा में 300 मीटर सीसी सड़क निर्माण लागत 9.50 लाख, भदरागुड़ा में 300 मीटर सीसी सड़क लागत 09.50 लाख का भूमिपूजन भी श्री देव ने किया। इस दौरान श्री देव ने ग्राम का सघन भ्रमण किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के घरों तक पहुँचकर जाकर सीधी बातचीत की। महतारी वन्दन योजना की हितग्राही महिलाओं से भी श्री देव ने चर्चा की और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के

साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जामावाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना में 140 स्वीकृति, पेंशन योजना में 225, भूमिहीन कृषि मजदूर 31, प्रधानमंत्री उज्वला गैस के 465, प्रधानमंत्री किसान निधि में 242 लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। गाँव, गरीब, किसान, महिला व युवाओं के विकास करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, महतारी वन्दन योजना, पेंशन योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर, पीएम सूर्य घर योजना, वीबी रामजी योजना हमारे गाँव के लोगों के विकास के उद्देश्य को पूरा करने को लागू की गई हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। श्री देव ने कहा कि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में जनता को लाभ मिला है ।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालक मण्डल की बैठक

- श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं उनके समग्र विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालक मण्डल की बैठक आज गुरूवार को नवा रायपुर स्थित मण्डल कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन द्वारा की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, श्रम विभाग उप-सचिव श्री विपुल गुप्ता, प्रभारी श्रमायुक्त श्री एस.एल. जांगड़े, नगरीय प्रशासन विभाग उप-सचिव श्री भागवत जायसवाल, एवं कल्याण आयुक्त श्री सुनील मिश्रा, भारत सरकार के प्रतिनिधि सहित मण्डल के सचिव श्री गिरीश रामटेके तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने अभी तक अपना पंजीयन नवीनीकरण नहीं कराया है, उनका शत-प्रतिशत पंजीयन 30 अप्रैल 2026 तक सतत् रूप से नवीनीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। श्रमिक बंधु से अनुरोध है कि, पंजीयन नवीनीकरण हेतु अपना आवेदन जिला श्रम कार्यालय, लोक सेवा केन्द्र, श्रमेव जयते मोबाईल एप्प एवं विभागीय पोर्टल बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उनके समग्र विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं मण्डल अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए आगे नवीनतम कदम भी उठाए जा रहे हैं। बैठक के दौरान मण्डल का वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाने तथा उनके कौशल के अनुरूप कार्य के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप विकसित किए जाने का अनुमोदन भी बैठक में दिया गया।

गाँव चलो-बस्ती चलो अभियान में उमड़ रहा कार्यकर्ताओं का हुजूम....

- भाजपा पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक सहित कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं गाँव-गाँव

रायपुर। संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं भाजपा स्थापना दिवस के प्रदेश संयोजक यशवंत जैन ने बताया है कि 'गाँव चलो-बस्ती चलो' अभियान में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी, जन प्रतिनिधि 50 चयनित गाँव में पहुँचकर लगातार लोगों से सीधा सम्पर्क कर रहे हैं साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिलकर उनका सम्मान कर रहे हैं।भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री जैन ने कहा कि भाजपा निर्धारित कार्यक्रम के तहत 7 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक यह अभियान चला रही है। 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। श्री जैन ने बताया कि केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत मंत्री, सांसद, विधायक सहित सभी जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के गाँवों और बस्तियों में जाएंगे। पार्टी के इस अभियान में सभी जन प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस अभियान तहत गाँव-गाँव जाकर जनता से मुलाकात करेंगे और सरकार की योजनाओं एवं नीतियों को समझाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव अपने विधानसभा क्षेत्र के गाँवों की बस्तियों में पहुँचकर लोगों से लगातार सम्पर्क कर रहे है, साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ को बता रहे हैं।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फिर ठगी

रायपुर। राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड इंजीनियर से 80 हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिए। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। आरोपी ने उन्हें झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दी और मामला खत्म करने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये की मांग की। डर के चलते पीड़ित ठग के झांसे में आ गए और बताए गए बैंक खाते में 80 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। कुछ देर बाद शक होने पर उन्होंने डीडी नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वन की समीक्षा की

जनता से जुड़ी सभी सेवाएं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में होना चाहिए

रायपुर/ संवाददाता

श्री विकासशील ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनके विभाग के अंतर्गत ऐसी सभी सेवाएं जो सीधे जनता से जुड़ी है, उन सभी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित की जाये तथा अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाईन किया जाये। समय सीमा में सेवाओं का लाभ हितग्राही को दिया जाए। समय सीमा में सेवाएं यदि नहीं दी जाती हैं तो संबधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिव की बैठक लेकर विभागों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभागीय सेवाओं के क्रियान्वन समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी सभी शासकीय सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना हैं। मुख्य सचिव ने प्रत्येक विभाग के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की । मुख्य सचिव ने अधिकारियों के कहा कि वे अपने विभाग के अंतर्गत और सेवाएं जो अधिनियम के अंतर्गत लायी जा सकती है, उन्हे चिन्हित कर अधिसूचित करना सुनिश्चित करें और सुशासन एवं अभिसरण विभाग को इसकी सूची उपलब्ध कराएं। बैठक में बताया गया की छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा की प्रभावी क्रियान्वन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही हैं। मुख्य सचिव ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों के अधिकारियो को विभागीय सेवओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने के लिए मार्ग दर्शन दिया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने प्रस्तुतिकरण के जरिए विभिन्न विभागों की लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। श्री भगत ने बताया की छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में जाकर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का अध्ययन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के परिपेक्ष में प्रदाय की जा रहीं समानान्तर सेवाओं एवं संबंधित विभागों की सेवाओं की सांकेतिक रूप से मैपिंग की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभाग की और सेवाओं को चिन्हित कर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करने प्रस्तावित करें। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, खनिज विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, ऊर्जा एवं जनसंपर्क के सचिव श्री रोहित यादव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., वाणिज्यिक कर (आबकारी) सुश्री आर. शंगीता, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, गामोउद्योग के सचिव श्री श्यामलाल धावड़े सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, वाणिज्यिक एवं उद्योग, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, श्रम, जल संसाधन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

संपादकीय

पश्चिम एशिया युद्ध भारत की चेतावनी-संवाद की कमी खतरनाक

कूटनीतिक तकाजे के साथ-साथ मानवीय पहलू से भी देखें, तो होर्मुज जलमार्ग को तत्काल खोलने की जरूरत है, अन्यथा वैश्विक पैमाने पर जिस तरह का ऊर्जा संकट खड़ा होगा, उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकेगी। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि पश्चिम एशिया में युद्ध ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन उसकी मार वैसे देशों को भी झेलनी पड़ रही है, जो किसी भी रूप में जंग में शामिल नहीं हैं। कई देशों में अब हालत यह है कि वहां तेल और गैस की कमी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने लगा है।भारत भी उन देशों में से एक है, जहां कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण आम लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जब से ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया है, तब से कई देशों में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। भारत में रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता भी काफी प्रभावित हुई है। यह स्थिति मुख्य रूप से होर्मुज जलमार्ग को रोके जाने के कारण सामने आई है और इसमें तभी राहत मिल सकती है, जब ईरान इस मार्ग को फिर से खोले वैश्विक स्तर पर यह चिंता गहरा रही है कि अगर होर्मुज जलमार्ग को इसी तरह बाधित करके रखा गया, तो आने वाले दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। शायद यही वजह है कि पश्चिम एशिया के इस संकट का हल निकालने की कोशिश के तहत ब्रिटेन की पहल पर साठ से ज्यादा देशों की बैठक हुई, जिसमें होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने और फंसे हुए जहाजों तथा चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में बिना बाधा के जहाजों की आवाजाही की अहमियत को रेखांकित किया गया, क्योंकि आज के दौर में समूची दुनिया में तेल और रसोई गैस लोगों के जीवन के सबसे अहम आधार बन चुके हैं। वहीं होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने के बाद से ही जिस तरह का ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, उसका भारत पर भी सीधा असर पड़ा है। जाहिर है, अन्य कई देशों की तरह भारत भी इस प्रयास में है कि जितना जल्दी हो, इस संकट का हल निकले और होर्मुज जलमार्ग को खोला जाए। बैठक में भारत ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए तनाव कम करने और सभी पक्षों के बीच संवाद के रास्ते पर लौटने की जरूरत है। यों भी, आज के दौर में कोई भी युद्ध सिर्फ उन देशों को प्रभावित नहीं करता, जिनके बीच वह लड़ा जा रहा होता है। अब यह वैश्विक चिंता का सवाल बन चुका है कि इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद ईरान ने रणनीतिक मोर्चे पर जो रुख अख्तियार किया है, उसका खमियाजा अब दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। संभव है कि अमेरिका और इजराइल को जवाब देने के लिए ईरान ने हमलों के अन्य मोर्चों के साथ-साथ होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया हो, लेकिन जो देश इस युद्ध में किसी भी पक्ष में नहीं हैं, अगर उन्हें इसकी मार झेलनी पड़ रही है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर विपरीत असर पड़ रहा है, तो इसे कैसे देखा जाएगा। विडंबना यह है कि ईरान और इजराइल-अमेरिका के बीच जारी युद्ध में संवाद को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। मगर कूटनीतिक तकाजे के साथ-साथ मानवीय पहलू से भी देखें, तो होर्मुज जलमार्ग को तत्काल खोलने की जरूरत है, अन्यथा वैश्विक पैमाने पर जिस तरह का ऊर्जा संकट खड़ा होगा, उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं की जा सकेगी।

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है।

पश्चिम बंगाल में बढ़ती अराजकता लोकतंत्र के लिए चुनौती

(ललित गर्ग)

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं। यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ़ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के

आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

विश्व शांति संकट- क्यों युद्ध और संघर्ष आज भी मनुष्य की प्राथमिकता हैं

(रितुप्रिया शर्मा)

मानव जीवन संघर्ष, प्रेम, शांति, इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता का एक अनूठा उदाहरण है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह बिना किसी भय के, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन जी सके और दूसरे को भी जीने दे। मगर आज की संस्कृति में अशांति के तत्व की प्रधानता होती जा रही है। न तो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कहीं शांति है, न ही राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं शांति की किरण नजर आती है। हर तरफ संघर्ष का शोर सुनाई देता है। युद्ध और टकराव को ही सबसे आखिरी हल मान लिया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी प्रश्न या समस्या का समाधान शांति ही है। शांति कोई असाधारण या अप्राप्य बात नहीं है। यह बहुत साधारण है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने आप में धीरज, प्रेम और भाईचारे के भाव को उत्पन्न करना होता है। मनुष्य की ईर्ष्या ही उसके इन भावों को बाहर आने से रोकती है और धीरे-धीरे न केवल वह खुद की शांति भंग करता है, बल्कि अपने आसपास की भी शांति को भंग करने लगता है। तात्कालिक तौर पर उसे जरूर लग सकता है कि अपनी मर्जी से वह जो कर रहा है, उससे उसे शांति मिल रही है, लेकिन वही वास्तव में उसके जीवन की अशांति का प्रबंध भी हो सकता है। यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर किसी मोहल्ले में आग लगती है, तो उसकी आंच और आग हमारे दरवाजे तक कभी भी आ सकती है।

दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन सबने शांति का ही पाठ पढ़ाया है और वह एक ऐसा पाठ है, जो अहिंसा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी से लेकर नेल्सन मंडेला तक, गौतम बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक, यहां तक कि कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक ने भी शांति के मार्ग को ही अपनाया। युद्ध, पीड़ा, लालसा, सब कुछ प्राप्त करने की होड़ मनुष्य को सही राह पर लेकर नहीं जाती, बल्कि इसके उलट उसे विनाश के कगार पर ले जाने में सक्षम है।

सवाल है कि शांति की इस स्थापित अहमियत और बड़े-बड़े प्रतीक महापुरुषों की शांति के लिए वकालत के बावजूद आज मनुष्य शांति के बजाय युद्ध को लेकर इतना उतावला क्यों रहता है। आज विश्व जिन आफतों से जूझ रहा है, वे सभी तकलीफें मनुष्य की ही निमंत्रित की हुई हैं। अपने आप को श्रेष्ठ कहलवाना, शक्ति को सर्वेसर्वा बना देना, मनुष्य को मनुष्य न समझकर उनकी जान की कोई कीमत नहीं आंकना, ये सभी बातें मनुष्यता के खिलाफ हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध से आज तक अनेक युद्ध लड़े गए, देशों ने हथियारों का विकास किया। इसमें आणविक हथियार भी शामिल थे, लेकिन डर अब इस बात का हो गया है कि कहीं कोई परमाणु शक्ति से संपन्न देश किसी अन्य देश के खिलाफ इनका इस्तेमाल न कर दे। बहुत सारे देशों ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इसके बावजूद परमाणु हथियार बनाने की होड़ बदस्तूर जारी है।

बड़े राष्ट्रों के डर से छोटे राष्ट्र भी अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में जुटे हुए हैं। बड़े राष्ट्रों का कहना है कि वे किसी अन्य राष्ट्र को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। वहीं छोटे राष्ट्र अपने बचाव के लिए अपने आपको परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं और यहीं से शुरू होती है विश्व में हथियारों की होड़, अशांति का माहौल और आम जनता की पीड़ा। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध इसी बात को उजागर करता है कि कमजोर अपने आपको मजबूत बनाना चाहता है और मजबूत अपने से कमजोर लोगों को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता। यह बात सही है कि परमाणु ऊर्जा का सदुपयोग होना चाहिए, न कि हथियारों की होड़ में इसका उपयोग। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण कर दें। ये मुद्दे शांति और भाईचारे से भी सुलझाए जा सकते हैं। बड़े राष्ट्रों को चाहिए कि वे छोटे देशों को आश्वस्त करें कि वे कभी भी उन पर आक्रमण नहीं करेंगे और उनको अपनी सुरक्षा के लिए आणविक हथियारों की ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जापान के हिरोशिमा-नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराने से उपजी त्रासदी का उदाहरण हमारे सामने है, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। क्या हम यह चाहते हैं कि विश्व वही स्थिति दोबारा देखे, जो उस वक्त हुई थी?

हममें से कोई भी यह नहीं चाहता कि विश्व में अशांति और असुरक्षा का माहौल पनपे और लगातार युद्धों की राजनीति में राष्ट्र अपने आपको झोंक दें। इससे न केवल समय और धन नष्ट होता है, बल्कि लोगों की जिंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती है। वर्षों से पाया हुआ राष्ट्रीय मुकाम धराशायी हो सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी लालसा को नियंत्रित करें, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। हमें अपने अंदर की इस कमी को दूर करना ही होगा। वरना भविष्य में मनुष्य जाति के सामने संकट और ज्यादा बड़ा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को हम ऐसा जीवन देकर जाएंगे, जो संसाधनविहीन होगा और उनकी प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे।

इसलिए हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत स्तर पर आपसी संघर्ष से और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गृहयुद्धों और महायुद्धों से दूर रहें, ताकि सभी लोग मिल-जुलकर तरक्की कर सकें और विश्व को शांति रूपी समाधान दे सकें।

वक्त जितनी तेजी से आगे भाग रहा है, उतनी ही तेजी से शायद समाज और लोगों की जीवनशैली में बदलाव भी हो रहा है। दो-ढाई दशक पहले तक ग्रामीण इलाकों में होने वाले शादी समारोहों में तस्वीर बिल्कुल अलग होती थी। वहां परिवार के साथ समाज होता था, केवल भोजन करने या समारोह में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि हर स्तर पर सब कुछ ठीक से निबाह देने में अपने स्तर पर हर सहयोग करने के लिए भी। शादी समारोह में शामिल सभी लोगों के लिए यह अपना आयोजन होता था। एक-दो पीढ़ी पहले के दौर में दो या तीन दिनों की अवधि के मुकाबले अब सब कुछ चंद घंटे में किसी विवाह भवन या 'बैंक्वेट' या 'विवाह भवन' में संपन्न हो जाता है। मगर अब भी कभी-कभी किसी शादी समारोह में पुराने दिनों की झलक मिल जा सकती है, जहां लोगों ने परंपरा को कायम रखने की कोशिश की।

भारत की जल समस्या केवल 'कितना पानी है' का सवाल नहीं, बल्कि 'कैसा पानी है' का भी सवाल

इसमें दोराय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक हैं, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जल नीति आपूर्ति बढ़ाने से आगे बढ़ कर मांग-प्रबंधन, जल गुणवत्ता, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल शासन पर जोर दे। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की चर्चा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि वर्ष 2012 में अद्यतन हुई नीति अब मौजूदा चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है।

(अलका 'सोनी')

हम सभी यह सुनते और जानते हुए बड़े हुए हैं कि जल है तो जीवन है। इसके बावजूद जल का अपव्यय करते हैं। जिस गति से संचय करने की बात की जाती है, उससे कई गुना पानी की बर्बादी होती है। कहीं भी सड़कों पर पानी बहते हुए देखा जा सकता है। यही कारण है कि भारत में जल संकट अब भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की कठोर सच्चाई है। देश के अनेक हिस्सों में भूजल स्तर नीचे जा चुका है, नदियां प्रदूषण से बेहाल हैं। शहरों की जल आपूर्ति व्यवस्था दबाव में है। लोग पानी के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा को भी इतना अनिश्चित बना दिया है कि कहीं बाढ़ और कहीं सूखा एक साथ दिखाई देता है। समस्या केवल पानी की कमी की नहीं है, असली संकट यह है कि प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं। जल संचय के लिए बनी नीतियों की धीमी गति और समाज के असंतुलित जल-व्यवहार के बीच आज भारत बुरी तरह उलझता जा रहा है।

भारत में जल संकट इसलिए भी जटिल है, क्योंकि यहां पानी का सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि कृषि, स्वास्थ्य, शहरीकरण, सामाजिक न्याय और शासन-व्यवस्था सबसे जुड़ा है। भूजल पर भारत की निर्भरता बहुत गहरी है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आकलन के अनुसार, वर्ष 2025 में देश की कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण क्षमता 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर आंकी गई, जबकि वार्षिक निकासी 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर रही। पहली नजर में यह संतुलित लग सकता है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रीय औसत के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन छिपा हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां निकासी सुरक्षित सीमा के आसपास या उससे ऊपर है, जबकि दूसरे क्षेत्रों में संसाधन अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। यही वजह है कि जल संकट पूरे देश में एक समान नहीं, बल्कि कई रूप में सामने आता है।

इसमें दोराय नहीं कि बांध, नहर, पाइपलाइन और बोरवेल आवश्यक हैं, लेकिन वे अकेले समाधान नहीं हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जल नीति आपूर्ति बढ़ाने से आगे बढ़ कर मांग-प्रबंधन, जल गुणवत्ता, पुनर्भरण, पुनर्चक्रण और स्थानीय जल शासन पर जोर दे। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन की चर्चा महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा है कि वर्ष 2012 में अद्यतन हुई नीति अब मौजूदा चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय के दस्तावेजों में भी यह स्वीकार किया गया है कि कम जल-उपयोग दक्षता, भूजल पर बढ़ता दबाव, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और फसल-पद्धति जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल नीति के पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी। मिहिर शाह समिति इसी उद्देश्य से गठित की गई थी।

बुनियादी सवाल यह है कि जब संकट इतना स्पष्ट है, तो सुधार की गति इतनी धीमी क्यों है! इसका उत्तर भारत की संघीय संरचना और जल शासन की जटिलता में छिपा है। जल राज्यों का विषय है। केंद्र दिशा दे सकता है, योजनाएं बना सकता है, वित्तीय सहायता दे सकता है, पर वास्तविक क्रियान्वयन राज्यों, स्थानीय निकायों और विभागीय तंत्र के माध्यम से ही होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नीयत से बनाई गई नीतियां भी जमीन तक पहुंचते-पहुंचते धीमी पड़ जाती हैं। ऊपर से पानी का प्रश्न राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी है। मुफ्त या सस्ती बिजली, सिंचाई, शहरी जलापूर्ति, उद्योगों की जरूरतें और राज्यों के जल विवाद ये सब मिल कर निर्णय को कठिन बना देते हैं।

कृषि इस बहस के केंद्र में है, क्योंकि भारत में जल उपयोग का सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में होता है। मगर कृषि को दोष देकर समस्या हल नहीं होगी। असल बात यह है कि दशकों से नीतिगत

ढांचा ही ऐसे फसल को बढ़ावा देता रहा है जो कई क्षेत्रों में जल-उपलब्धता के अनुकूल नहीं हैं। जहां पानी सीमित है, वहां भी धान या गन्ने जैसी फसलों की खेती जारी रहती है, जिसमें पानी की अधिक जरूरत होती है। इस परिस्थिति में यदि जल संरक्षण की बात की जाए, तो किसानों को विकल्प, तकनीक, सिंचाई, बाजार और मूल्य का आश्वासन भी देना होगा।

समस्या का दूसरा बड़ा कारण जल गुणवत्ता है। कई बार पानी उपलब्ध होता है, पर सुरक्षित नहीं होता। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की वार्षिक भू-जल गुणवत्ता रपट और संसद में सरकार द्वारा साझा जानकारी बताती है कि परीक्षण के लिए एकत्रित 28.3 फीसद नमूनों में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसी समस्याएं अभी भी गंभीर हैं। दिसंबर 2025 में साझा आंकड़ों के अनुसार 2024 के नमूनों में 3,415 में से 123 नमूनों में आर्सेनिक और 2,537 में से 24 नमूनों में सीसा अनुमेय सीमा से अधिक पाया गया। इसका मतलब साफ है कि भारत की जल समस्या केवल 'कितना पानी है' का प्रश्न नहीं, बल्कि 'कैसा पानी है' का भी प्रश्न है।

शहरी भारत में भी स्थिति कम चिंताजनक नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरों ने अपने स्थानीय जलस्रोतों जैसे तालाबों, झीलों, नालों और जलग्रहण क्षेत्रों को या तो पाट दिया है या उपेक्षित छोड़ दिया है। नतीजा यह हुआ कि शहर अब दूरदराज के स्रोतों, गहरे बोरवेल और टैंकरों पर निर्भर होते गए। यह व्यवस्था महंगी है और असमान भी। धनाढ्य इलाके में लोग पानी खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब बस्तियां अनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर रहती हैं। शहरों में सीवर और औद्योगिक अपशिष्ट का पर्याप्त शोधन न होने के कारण सतही जल स्रोत और भूजल दोनों प्रभावित होते हैं। यानी शहर अपने लिए पानी खींचते भी हैं और उसे प्रदूषित भी करते हैं। यह दोहरा दबाव भविष्य की शहरी जल सुरक्षा को और अधिक नाजुक बनाता है।

ग्रामीण भारत में तस्वीर अलग होते हुए भी उतनी ही गंभीर है। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनवरी 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मिशन के तहत 81.57 फीसद से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। यह उपलब्धि छोटी नहीं है। वर्ष 2019 में जहां केवल सीमित हिस्से तक नल-जल पहुंचा था, वहीं अब स्थिति काफी बदली है। मगर चुनौती यहीं समाप्त नहीं होती। पाइप के जरिए पानी देना एक बात है, नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना दूसरी बात है। कार्यक्षमता आकलन रपट भी इस बात की ओर संकेत करती है कि 'कनेक्शन' और 'भरोसेमंद सेवा' में फर्क है।

यही वह बिंदु है जहां समाज की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। भारत में पानी को अब भी असीमित संसाधन की तरह बरतने की प्रवृत्ति व्यापक है। घरों में अपव्यय, कालोनियों में वर्षाजल संचयन की उपेक्षा, भूजल के अनियंत्रित दोहन और स्थानीय जलस्रोतों के प्रति उदासीनता ये सब मिल कर संकट को गहरा करते हैं। दूसरी ओर, यही समाज समाधान का आधार भी बन सकता है। जहां पंचायतें, मोहल्ले, किसान समूह, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन मिल कर जलस्रोतों के पुनर्जीवन, तालाबों की मरम्मत और फसलों के विविधीकरण जैसे उपाय करते हैं, वहां परिणाम अधिक टिकाऊ दिखते हैं। नीतियां तभी सफल होती हैं, जब समाज उसे अपना कार्यक्रम समझे, केवल सरकारी योजना नहीं। हाल के वर्षों में जल बजट पर भी जोर बढ़ा है, जो इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं।

पानी का संकट दुनिया भर में गहराता जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर कुल उपलब्ध पानी का 97.5 फीसदी हिस्सा समुद्री है, बाकी 2.5 फीसदी हिस्सा मीठा जल है, लेकिन इसका भी काफी मात्रा प्रदूषित है, जो पीने योग्य नहीं है। एक अनुमान के अनुसार कुल जल का केवल एक फीसदी हिस्सा ही पीने योग्य है, जो दुनिया की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। ऐसे में जल संकट भयावह होता जा रहा है। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, जल प्रबंधन और संरक्षण खास तौर पर वर्षा जल संरक्षण के लिए कदम उठा रहा है, और इस दिशा में कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जल शक्ति मंत्रालय को लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने सहित पानी के दूसरे मुद्दों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए विभाग ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं, इसमें सबसे प्रमुख 2024 तक भारत के हर घर में पाइप से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।

घटना में प्रयुक्त थार वाहन को भी किया गया जप्त

बालिका को घर से अपहरण कर ले जाने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

कांकेर। अपहृता के पिता ने थाना अंतागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री को रंजन मिश्रा अपने 2 अन्य साथियों के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए मेरे घर से हाथ पकड़ कर खींच कर गाड़ी नंबर टी एस 08 एच के 9889 में बिठाकर ले जा रहे हैं, कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंतागढ़ के अपराध क्रमांक 21/2026 धारा 87, 333, 3(5) बीएनएस के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। टीम का गठन कर आरोपियों का पता तलाश एवं घेराबंदी कर केवटी भानुप्रतापपुर के पास पकड़ा गया जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार कर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पीड़ित बालिका कुछ महीने पहले बाहर काम करने हैदराबाद गई हुई थी, जब वह वहां से वापस आई उसके बाद से लगातार आरोपी रंजन मिश्रा जो कि हैदराबाद में उसी कंपनी में काम करता था उसके द्वारा पीड़िता को परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद पीड़िता से शादी करने के लिए रंजन मिश्रा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। हैदराबाद के दो आरोपी व एक कोरर निवासी रंजन मिश्रा पिता रमेश मिश्रा उम्र 26 वर्ष जाति ब्राह्मण साकीन मैगचाल थाना मैगचाल जिला संगारेड्डी हैदराबाद, प्रियांशु गुड्डू कुमार उपाध्याय पिता स्वर्गीय नालादय उम्र 21 वर्ष जाति ब्राह्मण साकीन मैगचाल थाना मैगचाल जिला संगारेड्डी हैदराबाद, लाली टेकाम पिता पीलाराम टेकाम उम्र 31 वर्ष जाति साकिन शीतला पारा थाना कोरर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अंतागढ़ रमेश जायसवाल, थाना प्रभारी भानुप्रतापपुर रामेश्वर देशमुख थाना अंतागढ़ से उप निरीक्षक हेमलता परिहार, प्रधान आरक्षक 886 नरेंद्र देव मांझी, महिला प्रधान आरक्षक 805 जमुना ठाकुर , आरक्षक 331 ईश्वर कोरेटी, आरक्षक 1078 रोशन लाल नेताम, आरक्षक 934 हरिशंकर मडावी, महिला आरक्षक 1104 हीरोदा दुग्गा, महिला आरक्षक 157 लोकेश्वरी गावडे एवं भानुप्रतापपुर थाना स्टाफ का सहयोग रहा।

सुकमा में लोकतंत्र की नई शुरुआत : बंदूक छोड़ मतपत्र थामा, अब पुनर्वासित युवा चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि

सुकमा। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्यधारा में लौट रहे आत्मसमर्पित युवाओं को अब लोकतंत्र से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक ऐतिहासिक पहल की है। सुकमा जिले के पुनर्वास केंद्र में निवासरत 116 हितग्राहियों का मतदाता परिचय पत्र (वोटर आईडी कार्ड) बनाकर उन्हें मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जिला शासन के इस सकारात्मक कदम से अब ये पुनर्वासित युवा अपने मताधिकार का प्रयोग कर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का चयन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को और मजबूत करते हुए अब वे भविष्य में स्वयं भी चुनाव लड़ने के पात्र बन गए हैं। यह बदलाव उनके जीवन में सम्मान, अधिकार और आत्मविश्वास की नई शुरुआत माना जा रहा है।

सरकार की नीति से बदली जिंदगी

जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का लाभ आत्मसमर्पित युवाओं को लगातार दिया जा रहा है। पुनर्वास केंद्र में निवासरत 116 हितग्राहियों के राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड पंजीयन के साथ-साथ पीएम आवास योजना सर्वे भी पूरा कराया गया है। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है।

कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

पुनर्वासित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण में 48 हितग्राही, सिलाई मशीन प्रशिक्षण में 5 हितग्राही, कृषि उद्यमी एवं राजमिस्त्री प्रशिक्षण में 265 हितग्राही, वाहन चालक प्रशिक्षण में 14 हितग्राही और मुर्गी पालन प्रशिक्षण में 25 हितग्राही कुल मिलाकर 317 पुनर्वासित युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जिला प्रशासन की यह पहल न केवल पुनर्वासित युवाओं को पहचान और अधिकार दिला रही है, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर भी कर रही है।

लो वोल्टेज से बेहाल खेत-खलिहान, 132 केव्ही सब स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर, अधिकारियों को लगाई फटकार

केशकाल। केशकाल के जामगांव में बन रहा 132 केवी सब स्टेशन अब राहत से ज्यादा लोगों के गुस्से की वजह बनता जा रहा है। एक तरफ पूरा केशकाल विधानसभा क्षेत्र इन दिनों लगातार लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कछुआ चाल से आगे बढ़ रहा है। लो वोल्टेज की समस्या से परेशान किसान आए दिन आंदोलन और धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि यह मुद्दा अब जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ चुका है। इसके बावजूद 132 केवी सब स्टेशन के निर्माण की धीमी गति कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते जनाक्रोश के बीच कोंडागांव कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना खुद केशकाल पहुंचीं और निर्माणाधीन सब स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और साफ निर्देश दिए कि बारिश से पहले हर हाल में काम पूरा किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि यह प्रोजेक्ट किसानों और आम जनता के लिए बेहद अहम है, क्योंकि लो वोल्टेज की समस्या से खेती-किसानी तक प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि कलेक्टर लगातार निरीक्षण कर इस पूरे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रही हैं, लेकिन उनके दबाव के बावजूद काम निर्धारित समयावधि से पहले पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह स्थिति अपने आप में सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब इस लेटलतीफी को लेकर विभाग के अधिकारियों से सवाल किया गया, तो वे मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। फिलहाल, जामगांव का 132 केवी सब स्टेशन विकास का वादा कम और प्रशासनिक सुस्ती व जवाबदेही की कमी की बड़ी मिसाल बनता जा रहा है।

आगामी शिक्षा सत्र में बुधपदर पोटाकेबिन में छात्र छात्राओं के लिए प्रारंभ होंगे आवासीय स्कूल कलेक्टर ने दिए निर्देश

दंतेवाड़ा। जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके तहत विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले पूर्ण करने पर जोर दिया गया है। इस क्रम में कलेक्टर ने पंचायत बुधपदर के गुमरगुडा, जपेडी पोटाकेबिन में बालिका एवं बालक शौचालय निर्माण, पानी की समुचित व्यवस्था हेतु नए बोर का खनन, सीट मरम्मत कार्य सहित अन्य आवश्यक कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विद्यालय में स्वच्छता बनाए रखने हेतु रेन वॉटर वाशिंग सिस्टम की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया, ताकि एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा बुधपदर पंचायत अंतर्गत इस 500 सीटर पोटाकेबिन को आगामी शिक्षा सत्र में संचालित किए जाने की योजना है। इसके अलावा कलेक्टर ने बड़ेकारका से कोड़नार तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए मिट्टी-मुरूम कार्य एवं 6 पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा।

नक्सल प्रभाव से विकास की ओर बढ़ा हेटारकसा, हर घर तक पहुंचा नल से जल

जल जीवन मिशन से बदली तस्वीर, 63 घरों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति

जगदलपुर। कभी नक्सल गतिविधियों के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहा कोयलीबेड़ा विकासखंड का ग्राम हेटारकसा अब तेजी से बदल रहा है। जहां पहले बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच मुश्किल थी, वहीं अब शासन की योजनाओं और सुरक्षा माहौल में सुधार के चलते गांव में विकास के नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। वर्षों तक नक्सल प्रभाव और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण बना रहा। पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या थी। गांव के लोग कुओं और नालों पर निर्भर थे, जिससे खासकर गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और बढ़ जाती थी। अब केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन और राज्य शासन के समन्वित प्रयासों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्राम हेटारकसा के 63 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए गए हैं। दो सोलर पंप आधारित जल टंकियों के माध्यम से प्रत्येक घर में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। गांव के निवासी राजनाथ पोटाई बताते हैं कि पहले पानी लाने के लिए दूर-दराज तक जाना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों अधिक लगता था। अब घर पर ही पानी उपलब्ध होने से दैनिक जीवन काफी सहज हो गया है। वहीं, ग्रामीण महिला सविता बेन के अनुसार, पहले दिन का बड़ा हिस्सा पानी की व्यवस्था में ही खर्च हो जाता था, लेकिन अब नल-जल सुविधा से उन्हें राहत मिली है और वे अन्य कार्यों पर ध्यान दे पा रही हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता का सकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। जलजनित बीमारियों में कमी आई है। साथ ही, ग्रामीण घरों के आसपास सब्जी उत्पादन भी कर रहे हैं, जिससे पोषण स्तर में सुधार के साथ अतिरिक्त आय के अवसर भी बढ़े हैं। नक्सल प्रभावित इस दूरस्थ क्षेत्र में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। ग्राम हेटारकसा की यह बदली हुई तस्वीर दर्शाती है कि सुरक्षा, विश्वास और विकास के समन्वित प्रयासों से सबसे कठिन क्षेत्रों में भी बदलाव संभव है।

जिला जेल सुकमा में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, फास्ट फूड प्रशिक्षण से बदलेगी जिंदगी

सुकमा। जिला जेल सुकमा में बंदियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल की जा रही है। जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को कौशल विकास के तहत विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, ताकि वे जेल से बाहर निकलने के बाद सम्मानजनक जीवन जी सकें। इसी क्रम में रायपुर से आई मास्टर ट्रेनर ज्योति पाल द्वारा 12 दिवसीय फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 35 बंदी भाग ले रहे हैं। उन्हें मोमोज, छोले-भटूरे, पानी पूरी, भेल पूरी, कचौड़ी, समोसा, नूडल्स, चाउमिन, सैंडविच, बर्गर, पुलाव और बिरयानी जैसे लोकप्रिय व्यंजन बनाना सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और बंदियों को प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे बंदियों ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया। बंदी दिर्दो महेश ने बताया कि उन्होंने फ्राइड राइस, चाइनीज पकौड़ा, गोभी चिली और मंचूरियन बनाना सीख लिया है। वहीं बंदी अशोक कुमार ने कहा कि वे मोमोज और पानी पूरी जैसे व्यंजन बनाना सीखकर भविष्य में स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। सहायक जेल अधीक्षक राजेश बिसेन ने बताया कि बंदियों को नई दिशा देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बंदियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए योग, साक्षरता अभियान और प्रेरणात्मक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। जिला जेल सुकमा की यह पहल बंदियों को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

यह कार्यक्रम प्रशासन की सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता का उदाहरण है।

नगर पंचायत उप निर्वाचन पखांजूर निर्वाचक नामावली तैयार करने कार्यक्रम जारी

कांकेर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगर पंचायत पखांजूर के उप निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति 09 अप्रैल तक किया जाकर निर्वाचक नामावली की प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर, तहसीलदार पखांजूर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत पखांजूर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के विधानसभा की अद्यतन निर्वाचक नामावली प्राप्त करने के बाद विधानसभा की निर्वाचक नामावली को वार्डवार पृथक कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली को वार्डवार एवं भागवार मार्किंग की जाएगी। वार्डवार एवं भागवार चिन्हित निर्वाचकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के संबंधित भाग के अनुभाग में 10 अप्रैल तक शिफ्ट किया जाएगा तथा 11 अप्रैल तक निर्वाचक नामावली के पीडीएफ तैयार करके जांच कर त्रुटि का सुधार किया जाएगा एवं चेकलिस्ट संशोधन पश्चात प्रारूप निर्वाचक नामावली मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा और जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 13 अप्रैल तक निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराया जाकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां 13 अप्रैल से 20 अप्रैल के दोपहर 03 बजे तक प्राप्त की जाएगी। दावा आपत्ति निपटारे की अंतिम तारीख 23 अप्रैल निर्धारित की गई है। प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल शुक्रवार निर्धारित की गई है।

पीढ़ियों का अनमोल संगम : खेल उत्सव में बुजुर्गों के साथ खिलखिला उठा बचपन

जगदलपुर। रिश्तों की गर्माहट और बचपन की शरारतों का एक ऐसा अनूठा संगम पिछले तीन दिनों से जिले की विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में देखने को मिला, जिसने आधुनिकता की भागदौड़ के बीच पारिवारिक जुड़ाव की एक नई मिसाल पेश की है। बीते 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोजित दादा-दादी, नाना-नानी खेल उत्सव ने न केवल आंगनवाड़ी के बच्चों, बल्कि उनके अभिभावकों और घर के बुजुर्गों के जीवन में भी उत्साह का नया संचार कर दिया। इस आयोजन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 126 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कार्यक्रम को बेहद व्यवस्थित और यादगार बनाया। उत्सव का आगाज अत्यंत भावपूर्ण रहा, जहाँ नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपनी परंपरा और संस्कृति का परिचय देते हुए अपने दादा-दादी और नाना-नानी का स्वागत आरती, तिलक और फूलों के गुलदस्ते भेंट कर किया। बच्चों के छोटे-छोटे हाथों से सम्मानित होकर बुजुर्गों की आँखें खुशी से छलक उठीं और पूरा वातावरण प्रेम व आदर की खुशबू से सराबोर हो गया। स्वागत की इस बेला के बाद शुरू हुआ खेलों और मनोरंजन का वह सिलसिला, जिसने उम्र के फासले को पूरी तरह मिटा दिया। खेल के मैदान में उतरे दादा-दादी और नाना-नानी ने बच्चों जैसी ऊर्जा दिखाते हुए म्यूजिक चेयर, रस्साकशी और चम्मच-दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं डांस, पेपर कप और ब्लॉक बनाने जैसी गतिविधियों में बुजुर्गों और बच्चों की जुगलबंदी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस पूरे उत्सव का सबसे भावुक और रोमांचक क्षण वह रहा, जब आँखों पर पट्टी बाँधकर अपने बच्चों को पहचानने की गतिविधि आयोजित की गई।

इस अनूठे खेल ने यह सिद्ध कर दिया कि पीढ़ियों के बीच का रिश्ता केवल देखने तक सीमित नहीं

महतारी वंदन योजना के तहत हितग्राहियों का ई-केवायसी कराने की अपील

कांकेर। राज्य शासन द्वारा समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का ई-केवायसी कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना के तहत लाभान्वित समस्त महिलाओं का ई-केवायसी कराया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 01 लाख 80 हजार महिलाओं को प्रतिमाह लाभान्वित किया जा रहा है, इनमें से लगभग 27 हजार महिलाओं का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार जिले में महतारी वंदन योजना से लाभान्वित लगभग 01 लाख 53 हजार हितग्राहियों का ई-केवायसी कराया जाना है। इन महिलाओं के नाम, सूची संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महतारी वंदन एप के लॉगिन आईडी में उपलब्ध है। केवल इन्हीं महिलाओं का ई-केवायसी निकट के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर निःशुल्क कराया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य स्तर से चिप्स को नोडल एजेंसी बनाते हुए उनके अधीनस्थ संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उक्त कार्य निःशुल्क कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही सभी परियोजनाओं में व्हीएलई एवं पर्यवेक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा चुका है। महतारी वंदन योजना से लाभान्वित ऐसी समस्त महिलाएं जिनका ई-केवायसी नहीं हुआ है उन्हें आवश्यक अभिलेखों जैसे अद्यतन आधार कार्ड की मूलप्रति एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता से महतारी वंदन योजना का हितग्राही पंजीयन क्रमांक प्राप्त कर निकट के कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में अपना ई-केवायसी कराने कहा गया है।

रण ऑफ कच्छ की वीरता को नमन : 219वीं बटालियन सीआरपीएफ ने मनाया 61वां शौर्य दिवस

कोंटा। इंजराम स्थित 219वीं बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय में 61वां शौर्य दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कमांडेंट पार्थ सारथी घोष ने संबोधित करते हुए बताया कि 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के रण ऑफ कच्छ के सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान की ब्रिगेड ने हमला किया था, जहां सीआरपीएफ की मात्र दो कंपनियों के जवानों ने अदम्य साहस दिखाते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस संघर्ष में 6 जवान शहीद हुए, जबकि 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 4 को जीवित पकड़ा गया, जिसके बाद दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह दिन जवानों के साहस और बलिदान की ऐतिहासिक मिसाल है, जिसे सम्मान देने के लिए हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। कमांडेंट ने जवानों से देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी राहुल आर., उप कमांडेंट अभय कुमार श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट कानाराम चौधरी सहित अधीनस्थ अधिकारी एवं सभी जवान उपस्थित रहे।

पैरी पखना गांव में कलेक्टर की चौपाल, हर महीने के तीसरे सोमवार को होगा स्वास्थ्य शिविर

जगदलपुर। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड के सुदूर अंचल स्थित ग्राम पंचायत करका के पैरी पखना गाँव में कलेक्टर आकाश छिकारा ने चैपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित इस गाँव तक पहुंचने के लिए कलेक्टर ने सुकमा जिले के बंकेपाल तक चारपहिया वाहन से यात्रा की, इसके बाद पैदल और मोटरसाइकिल से कठिन रास्ता तय कर गाँव पहुँचे। गाँव पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से कलेक्टर आकाश छिकारा और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन का स्वागत किया। चौपाल के दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए मोबाइल कनेक्टिविटी, राशन व्यवस्था, आधार कार्ड निर्माण, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, राशन दुकान, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग रखी। इस पर कलेक्टर ने कहा कि पूर्व में माओवाद गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन अब हालात में सुधार के साथ विकास कार्यों को तेजी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रस्ताव भेजा गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिविर आयोजित किया जाए, वहीं हर महीने के तीसरे सोमवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। उन्होंने ग्रामीणों को वन अधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महतारी वंदन योजना और मातृ वंदन योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही पशुपालन और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं से लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।

संक्षिप्त समाचार

आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती आवेदन 23 अप्रैल तक

बिलासपुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना बिलासपुर अंतर्गत शहर के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 20 कुदुदंड मातापारा के पास, 223 फेकट पारा कतियापारा, 111 निराला नगर कतियापारा एवं 124 लोधीपारा नाकापारा में सहायिका के 1-1 रिक्त पदों पर 23 अप्रैल तक वेबसाइट https//aww.e-bharti.in/login में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्क्रैप निपटान में 303.47 करोड़ का राजस्व अर्जन कर रचा कीर्तिमान!

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में मिशन जीरो स्क्रैप के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए स्क्रैप के निपटान से ?303.74 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि रेलवे के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी स्क्रैप बिक्री है। उल्लेखनीय है कि यह आय रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित ?270 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य से 12.4ब अधिक है, जो संगठन की कुशल कार्यप्रणाली, प्रभावी योजना एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को दर्शाता है। यह सफलता विभिन्न कार्य स्थलों एवं ट्रैक किनारे पड़े स्क्रैप की सुनियोजित पहचान, उसके व्यवस्थित एकत्रीकरण तथा ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त की गई है। इस पहल से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, बल्कि रेलवे परिसरों की स्वच्छता एवं सुव्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्क्रैप बिक्री के मद-वार विवरण में रेल से ?114.96 करोड़, पी.वे. आइटम से ?16.53 करोड़, रोलिंग स्टॉक्स से ?32.53 करोड़, नॉन-फेरस सामग्री से ?25.63 करोड़, पीएससी स्लीपर से ?8.39 करोड़ तथा अन्य मदों से ?105.43 करोड़ की आय अर्जित की गई है। इसके साथ ही, भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (त्द्रू) के माध्यम से खरीद में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्द्रू के माध्यम से ?397.83 करोड़ की खरीद की गई, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 37.80ब अधिक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यह उपलब्धि केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठन की दूरदर्शिता, पारदर्शिता, संसाधनों के कुशल प्रबंधन एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। यह सफलता भविष्य में और भी उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है।

जुठही अंडरब्रिज में सड़क मरम्मत कार्य कार्य प्रगति पर

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत जयरामनगर स्टेशन-लटिया केबिन के मध्य किमी. 696/17-19 पर स्थित रुह्य नं-356 (जुठही अंडरब्रिज) पर सड़क आवागमन को और अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अति आवश्यक सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य के फलस्वरूप इस अंडरब्रिज को दिनांक 25 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक तक सड़क यातायात के लिए पूर्णत: बंद रखा गया है। परंतु कार्य के दौरान कुछ अतिरिक्त तकनीकी कार्य जुड़ जाने के फलस्वरूप अब इस समपार को सड़क यातायात हेतु दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक पूर्णत: बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में सड़क यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग के रूप में पाराघाट अंडरब्रिज (रुह्य-359) एवं समपार संख्या 355 (कल्याणपुर फाटक) का उपयोग किया जा सकता है। रेल प्रशासन आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट करता है एवं सहयोग की आशा करता है।

रायपुर में सर्वधर्म मिलन समारोह का भव्य आयोजन

भाईचारे,सौहार्द और राष्ट्रीय एकता का दिया गया संदेश

बिलासपुर। भारतीय पत्रकार संघ एवं स्टार वैदिक वेलफेयर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 7 अप्रैल 2026, मंगलवार को सिविल लाइन स्थित वृन्दावन हॉल में भव्य सर्वधर्म मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में धार्मिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन संजय शर्मा ने किया, जिन्होंने पूरे आयोजन को गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा जी उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों के रूप में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग अध्यक्ष ईला गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी, बृजेश चौबे जी, पूर्व महासचिव संदीप पुराणिक जी, प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, उपाध्यक्ष दिलीप साहू जी, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु जी तथा संयुक्त सचिव भूपेश जांगड़े जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा जनघोषणा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय प्रकाश शुक्ला जी, डॉ. उदयभान सिंह चौहान जी, लक्ष्मीनारायण लाहोटी जी, नरेन्द्र पाण्डेय जी, पी.सी. रथ जी, सुधीर तम्बोली जी, प्रदीप दुबे जी, स्मार्ट सिनेमा के संपादक पी.एन. लकी जी, बंगबंधु के संपादक हैरी बैरागी जी, बी-फेर न्यूज़ के संपादक आनंद गुप्ता जी, भारतीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल समिम, भारतीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश सचिव परितोष शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संरक्षक मो जीशान विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए स्टार वैदिक वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष सैयद सलमा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सर्वधर्म मिलन समारोह समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी सम्मान की भावना

को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति विविधता में एकता की मिसाल है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं फाउंडेशन की महासचिव श्रीमती आशा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और आपसी विश्वास को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि जब अलग-अलग धर्मों के लोग एक मंच पर आकर मानवता और शांति का संदेश देते हैं, तब समाज में नई ऊर्जा और सद्भाव का वातावरण बनता है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने समाज में आपसी सहयोग, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर समाजिक संस्था एवं वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया जिसमें दावतें ए इस्लामी मोहसिन ए आजम मिशन को बेहतरीन समाज सेवा के लिए पुरसकृत किया गया दावतें ए इस्लामी से मो शहज़ाद अत्तारी मो कासिम अत्तारी को इनाम से नवाजा गया वहीं मोहसिन ए आजम मिशन से मो आरिफ मो फहीम अब्दुल आबिद रफीक तालिब मो रौशन गुलाम हसन रूमी हाजी मो जाकिर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन स्थान के लिए सैय्यद स ईद जी इंडियन पब्लिक स्कूल का सम्मान किया गया समाज सेवा के लिए नवापारा मस्जिद के अल्तमस सिद्दकी जमात ए इस्लामी से मो शोहेब भाई को सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रिया सेन आशु परवीन महिला पत्रकारों में मोनल दीदी विनिता मंडल शगुफ्ता शिरिन ज्योति राय सुधा बाघ सीमा दुबे वंदना पाटले रोमा दीदी सहीत सभी वरिष्ठ पत्रकार सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे

राजस्व पखवाड़ा शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण,ग्रामीणों की समस्याएं मौके पर सुनीं..

बिलासपुर। जिले में चल रहे राजस्व पखवाड़ा के तहत कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्राम गनियारी में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने मौके पर समस्याएं सुनकर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए और अधिकारियों को सक्रियता बढ़ाने को कहा। जिले में संचालित राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ग्राम गनियारी (उप तहसील गनियारी) में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विशेष रूप से राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र समाधान पर जोर दिया। साथ ही जल संचयन एवं संरक्षण के महत्व को बताते हुए

ग्रामीणों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने गांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। शिविर में राशन कार्ड प्रतिवेदन, फौती नामांतरण, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र, तथा नाम त्रुटि सुधार से संबंधित आवेदनों पर कार्यवाही की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भरनी-परसदा में आयोजित राजस्व पखवाड़ा शिविर का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही सरपंच, जनप्रतिनिधि, किसान और बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी शिविर में शामिल हुईं।

सफलता की कहानी खीरा की खेती से बदली सुभद्रा की जिंदगी

बिलासपुर। कोटा के ग्राम करका की सुभद्रा ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन, समूह की शक्ति और मेहनत साथ हो, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना आसानी से साकार किया जा सकता है। सुभद्रा समूह से जुड़कर खीरा की खेती कर आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ अब लखपति दीदी बन चुकी है ,सुभद्रा मुख्यमन्त्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सरकारी योजना ने उनका जीवन बदल दिया है। आदिवासी बहुल गांव करका की सुभद्रा आर्मो ने आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत मां सरस्वती समूह से जुड़कर खीरा की खेती को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया। शुरुआत में समूह को 15,000 रुपये ऋण, 60,000 रुपये इक्विटी तथा 3,00,000 रुपये बैंक ऋण प्राप्त हुआ। इस आर्थिक

सहयोग ने महिलाओं को खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में बड़ी मदद दी। समूह की महिलाओं ने मेहनत, लगन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाते हुए खीरा की खेती शुरू की। उनकी मेहनत का परिणाम यह है कि आज वे 2 एकड़ में खेती कर लगभग 10 क्विंटल खीरा की बिक्री हर दूसरे दिन कर रही हैं। इससे उन्हें लगभग 7,000 रुपये की आय प्राप्त हो रही है। इस अतिरिक्त आय से समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। अब वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रही हैं, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं और भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं। सुभद्रा बताती हैं कि इस सफलता के पीछे समूह की बीमा सखी हबीबुन निशा का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहा, जिन्होंने समय-समय पर महिलाओं को बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता प्रदान कर ऋण सबंधी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता की साथ ही खेती की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सूटकेस में छुपा कैश कांड! रेलवे स्टेशन के पास 17.90 लाख के साथ संदिग्ध गिरफ्तार

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब टेंगनमाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध युवक दो सूटकेस और एक पिट्ठू बैग के साथ चक्कर काटते हुए पकड़ा गया और जब बैग खुले तो अंदर से निकले नोटों के बंडल देखकर पुलिस टीम भी चौंक गई, पूरा मामला 8 अप्रैल 2026 का है जब चौकी बेलगहना पुलिस और ए.सी.सी.यू. बिलासपुर की संयुक्त टीम इलाके में गश्त और अपराध विवेचना में जुटी थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में भारी सामान के साथ घूम रहा है, सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट किया और दिशा-निर्देश लेकर मौके पर घेराबंदी की, पुलिस ने टेंगनमाड़ा रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध को दबोच लिया, पूछताछ में उसने अपना नाम पवन बजाज पिता अर्जुन बजाज उम्र 35 वर्ष निवासी कश्यप कॉलोनी पुराना बस स्टैंड थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर बताया, जब उसके पास मौजूद दो सूटकेस और एक बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 10, 20 और 50 रुपये के नए नोटों के कुल 81 बंडल मिले जिनकी कुल कीमत 17 लाख 90 हजार रुपये निकली, इतनी बड़ी नकदी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल इसे संदिग्ध मानते हुए धारा 106 बीएनएसएस के तहत पूरी रकम जब्त कर ली, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी भारी रकम आखिर आई कहां से और इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होना था, पुलिस फिलहाल पवन बजाज से रकम के स्रोत और संभावित आपराधिक कनेक्शन की गहन पूछताछ कर रही है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल नागपुर की तत्परता:वंदे भारत में खोई सोने की बाली 'ऑपरेशन अमानत' के तहत यात्री को लौटाई

- ऑपरेशन अमानत की सफलता : वंदे भारत एक्सप्रेस में खोया कीमती आभूषण सुरक्षित बरामद दपूमरे

बिलासपुर। दिनांक 08.04.2026 को गाड़ी संख्या 20826 वंदे भारत एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के कान की सोने की बाली खो जाने की शिकायत रेलमदद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई। इस पर रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अनुरक्षण दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन अमानत के तहत बाली को खोजकर संबंधित यात्री को सुरक्षित सुपुर्द कर अपनी ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट परिचय दिया। रेलवे में यात्रा के दौरान अक्सर यात्री अपना सामान ट्रेन या रेलवे परिसर में भूल जाते हैं अथवा खो देते हैं। ऐसी स्थिति में यात्री रेलमदद (139), रेलवे सुरक्षा बल, जी आर पी या अन्य रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ऑपरेशन अमानत के अंतर्गत खोए या छूटे सामान की खोजबीन कर उसे सही मालिक तक पहुँचाने की कार्रवाई की जाती है। श्री दीप चंद्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, नागपुर मंडल के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में मिले अथवा खोजे गए सामान को सत्यापन उपरांत संबंधित यात्री को सौंपा जाता है। इसी क्रम में प्राप्त शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता की माता श्रीमती चित्रा, जो नागपुर से गोंदिया तक यात्रा कर रही थीं, उनका एक सोने का ईयररिंग यात्रा के दौरान कहीं गिर गया था। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल

अनुरक्षण दल में तैनात आरक्षक वी.पी. सिंह ने तत्काल कोच संख्या ब्व-1 में खोजबीन कर उक्त सोने की बाली बरामद की। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत सुरक्षा नियंत्रण कक्ष नागपुर एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया को दी। दिनांक 09.04.2026 को गाड़ी संख्या 22647 तिरुअनंतपुरम एक्सप्रेस से वापसी के दौरान उक्त बाली त्र्क्क पोस्ट गोंदिया को सुपुर्द की गई। सूचना मिलने पर शिकायतकर्ता श्री मनोज जेठानंद मनुजा (उम्र 44 वर्ष, निवासी हरिकाशी नगर, गोंदिया) रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया में उपस्थित हुए। आवश्यक सत्यापन के पश्चात लगभग ?36,000 मूल्य की सोने की बाली उन्हें सुरक्षित वापस सौंप दी गई। यात्री द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अनुरक्षण दल एवं रेलवे सुरक्षा बल गोंदिया के इस सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें तथा किसी भी प्रकार की असुविधा या सामान खोने की स्थिति में तुरंत रेलमदद हेल्पलाइन 139 या निकटतम रेलवे अधिकारी से संपर्क करें।-

एसईसीएल की मेजबानी में तीसरे कोल इंडिया एचआर आईआर कॉन्क्लेव 'उत्कर्ष 2026' का उद्घाटन संपन्न....

- दो दिवसीय कॉन्क्लेव में जुटे हैं कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों के एचआर अधिकारी, एचआर/आईआर से जुड़े विषयों पर होगा गहन मंथन

बिलासपुर। साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (स्श्वष्टरु) की मेजबानी में आयोजित दो दिवसीय कोल इंडिया एचआर/आईआर कॉन्क्लेव 'उत्कर्ष 2026' का उद्घाटन आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को एसईसीएल वसंत विहार स्थित वसंत क्लब में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन में कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंधों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन करेंगे। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि कोल इंडिया चेयरमैन श्री बी. साईराम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कोयला देश की ऊर्जा का आधार है और हमारे कर्मचारी हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कोल इंडिया Reform, Perform, Transform के रूप में मना रहा है और इस विज़न को साकार करने में हमारे कर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वागत उद्बोधन में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा कि एसईसीएल के लिए इस प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव की मेजबानी करना अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था के लिए उसके कर्मी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और उनके विकास एवं कल्याण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक

हैं। विशेष संबोधन में कोल इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कोल इंडिया केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक पहचान है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि जो जीता वही कोल इंडियन और सभी को इस संगठन का हिस्सा होने पर गर्व होना चाहिए। कॉन्क्लेव के कीनोट सत्र में मुख्य वक्ता कोल इंडिया के निदेशक (मानव संसाधन) डॉ. विनय रंजन ने कहा कि स्थापना के बाद से कोल इंडिया में व्यापक परिवर्तन आया है। आज संगठन अपने कर्मियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कार्यस्थल पर संवाद और संवेदना को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए कहा कि इससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और हितधारकों की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है। उद्घाटन सत्र के दौरान कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के निदेशक (मानव संसाधन), स्श्वष्टरु के निदेशकगण तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संवाद सत्र के अंत में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों की एचआर टीमों द्वारा नवाचारों पर प्रस्तुतियाँ भी दी गई। इस दो-दिवसीय सम्मेलन में कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के 100 से अधिक मानव संसाधन अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान देश के प्रतिष्ठित एचआर विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता साझा की जाएगी, जिससे प्रतिभागियों को नवीन दृष्टिकोण एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होगा।

एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 01-01 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन

बिलासपुर। ग्रीष्मकालीन के दौरान यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एलटीटी-हावड़ा-एलटीटी के मध्य 01-01 फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है । गाड़ी संख्या 01145 एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन एलटीटी से दिनाँक 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को चलेगी 7 इसी प्रकार गाड़ी संख्या 01146 हावड़ा-एलटीटी स्पेशल ट्रेन हावड़ा से दिनाँक 16 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को चलेगी 7 इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया, दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर स्टेशनों में दिया गया है गाड़ी की समय सारिणी गाड़ी संख्या 01145 एलटीटी-हावड़ा स्पेशल ट्रेन एलटीटी से दिनाँक 14 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को 20.15 बजे रवाना होगी तथा ठाणे आगमन 20.40 बजे, प्रस्थान 20.43 बजे, कल्याण आगमन 21.07 बजे, प्रस्थान 21.10 बजे दूसरे दिन नासिक रोड आगमन 00.15 बजे, प्रस्थान 00.18 बजे, भुसावल आगमन 03.35 बजे, प्रस्थान 03.40 बजे, अकोला आगमन 05.55 बजे, प्रस्थान 05.57 बजे, बडनेरा आगमन 07.55 बजे , प्रस्थान 07.58 बजे, नागपुर आगमन 10.15 बजे, प्रस्थान 10.20 बजे, गोंदिया आगमन 12.04 बजे, प्रस्थान 12.06 बजे, दुर्ग आगमन 14.15 बजे, प्रस्थान 14.20 बजे, रायपुर आगमन 14.55 बजे।

शरीर में हार्मोन संतुलित करने के लिए रोज सुबह जरूर पिएं ये ड्रिंक, दूर होंगी कई समस्याएं

स्वस्थ रहने के लिए शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस रहना भी बेहद जरूरी होता है। अगर आपके हार्मोन्स असंतुलित हो गए हैं तो संभव है कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे बैलेंस रखने के लिए लोग तरह-तरह के नुस्खे अपनाते हैं। कुछ लोग तो इसके लिए दवाओं का भी सेवन करते हैं। जबकि आप घर पर बनी मात्र एक हेल्दी ड्रिंक पीकर भी हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आइये डाइटिशियन ऋचा गंगानी से जानते हैं इस ड्रिंक को पीने से हार्मोन्स कैसे नियंत्रित होते हैं और इसे बनाने का तरीका।

कैसे बनाएं ये ड्रिंक?

- यह ड्रिंक बनाना काफी आसान है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
- इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको घी और नारियल का तेल लेना है।
- अब इसके बाद आपको हल्दी और काली मिर्च लेनी है।
- यह सामग्रियां जुटाने के बाद आपको एक गिलास पानी गर्म करना है।
- अब गर्म पानी में सबसे पहले एक चम्मच घी मिलाएं। इसके बाद इसमें अन्य सामग्रियां डालें।
- इस ड्रिंक एक साथ मिलाकर आप सुबह खाली पेट इसे पी सकते हैं।

हार्मोन्स बैलेंस करने में मददगार

अगर आपको हार्मोनल इबैलेंस की समस्या है तो ऐसे में इस ड्रिंक को जरूर पिएं। इसमें घी और हल्दी की मात्रा होती है, जो शरीर में हार्मोन्स के उत्पादन को कंट्रोल करने के साथ ही उसे बैलेंस रखने में भी मदद करती है। यह ड्रिंक शरीर में होने वाले ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करके हार्मोन्स के इबैलेंस को कम करने में मददगार साबित होती है। सुबह के समय घी खाने से शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल बैलेंस रहता है।

इस ड्रिंक को पीने के अन्य फायदे

- यह ड्रिंक सेहत के लिए अन्य भी कई तरीकों से फायदेमंद साबित होती है।
- अगर आप वजन घटाना चाहते है तो भी इस ड्रिंक को पी सकते हैं।
- इसे पीने से पाचन प्रक्रिया तेज होने के साथ ही मेटाबॉलिज्म भी दुरुस्त रहता है।
- इस ड्रिंक को पीने से शरीर की थकान दूर होती है साथ ही उर्जा की कमी महसूस नहीं होती है।

गर्मियों में बढ़ जाता है टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन का जोखिम

गर्मी में बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है। वैसे तो स्किन इंफेक्शन के लक्षण बहुत ही आम होते हैं, लेकिन कुछ इंफेक्शन ऐसे भी होते हैं, जो कुछ ही लोगों को होते हैं। इन्हीं इंफेक्शन में से एक है टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन। टिनिया नाइग्रा इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव करने के लिए क्या किया जा सकता है

गर्मी के मौसम में तेज धूप, लू, पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से स्किन इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको अपनी लाइफ में किसी तरह का स्किन इंफेक्शन जरूर होता। विशेषकर गर्मी में बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होना बहुत ही आम बात है। वैसे तो स्किन इंफेक्शन के लक्षण बहुत ही आम होते हैं, लेकिन कुछ इंफेक्शन ऐसे भी होते हैं, जो कुछ ही लोगों को होते हैं। इन्हीं इंफेक्शन में से एक है टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन। टिनिया नाइग्रा इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव करने के लिए क्या किया जा सकता है।

क्या है टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन

टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन एक दुर्लभ प्रकार का फंगल इंफेक्शन है। यह इंफेक्शन मुख्य रूप से पैरों के तलवे और हथेलियों को प्रभावित करता है। कुछ मामलों में यह इंफेक्शन पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है। गर्मी के मौसम में जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, उन्हें नाइग्रा इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन शरीर पर काले धब्बे की तरह विकसित है। कुछ केस में इसके धब्बे भूरे और लाल भी हो सकते है।

टिनिया नाइग्रा इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं

टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन त्वचा पर खुरदरे, भूरे या काले धब्बे के रूप में दिखाई दे सकता है। शुरुआत में कुछ लोग टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन को स्किन कैंसर समझने की भूल कर सकते हैं, क्योंकि यह समय के साथ बड़ा होता जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से आपके कई भ्रम दूर हो सकते हैं। टिनिया नाइग्रा काला धब्बा त्वचा के कैंसर से अलग होगा क्योंकि इसका आकार अजीब होता है। यदि आपके हाथों पर टिनिया नाइग्रा है, तो आप पाएंगे कि इसका रंग पूरे दिन बदलता रहता है। यह सुबह के समय गहरे भूरे रंग से लेकर शाम के समय हल्के रंग तक हो सकता है। इस इन्फेक्शन के लक्षण हथेलियों पर दिनभर काम करने और आपने किस तरह की चीजों को छुआ है, इस पर आधारित हो सकते हैं। यह इंफेक्शन आमतौर पर हाथों की हथेलियो और पैरों के तलवों को प्रभावित करता है। कुछ मामलों मे यह गर्दन पर भी विकसित हो सकता है। चूंकि टिनिया नाइग्रा इंफेक्शन के कारण ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती है, इसलिए इस इंफेक्शन का पता बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है।

टिनिया नाइग्रा होने का कारण क्या है

यह स्किन इन्फेक्शन हॉर्टिया वर्नेकी नामक कवक के संपर्क में आने के बाद होता है। हॉर्टिया वर्नेकी अत्यधिक खारे वातावरण या अत्यधिक उच्च नमक सामग्री वाले स्थानो पर पनपता है। टिनिया नाइग्रा की ऊष्मायन अवधि लंबी होती है। इसका मतलब यह है कि हॉर्टिया वर्नेकी के संपर्क में आने के बाद यह तुरंत दिखाई नहीं देता है। फंगस के संपर्क में आने के कम से कम 2 से 7 सप्ताह बाद आप अपनी त्वचा के रंग में बदलाव देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि टिनिया नाइग्रा इन्फेक्शन के लक्षण देरी से नजर आते हैं।

टिनिया नाइग्रा का इलाज क्या है

यदि आपको लगता है कि आपको टिनिया नाइग्रा है, तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट यह जानने के लिए संक्रमित क्षेत्र का एक नमूना लेंगे कि आपको टिनिया नाइग्रा है या नही। यदि आपके टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो आप एंटीफंगल स्किन क्रीम के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। 2 से 4 सप्ताह के लगातार उपयोग के बाद एंटी फंगल स्किन क्रीम आपके टिनिया नाइग्रा को ठीक कर देगी।

आप भी पीते हैं नमक वाली चाय?

जानें इससे होने वाले गंभीर नुकसान

चाय में दूध के साथ नमक मिलाकर पीने से अपच, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर समेत कई गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

चाय भारत में पानी के बाद सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक है। इसका सेवन बड़े-बूढ़ों से लेकर बच्चे भी करते हैं। चाय का मार्केट इतना बड़ा है कि दुनियाभर मे अलग-अलग तरह की चाय मिलती है। आमतौर पर लोग दूध वाली चाय का ही सेवन करते है। भारत मे मसाला चाय और हर्बल चाय का भी चलन है। सावधानीपूर्वक और सही तरीके से चाय का सेवन करने से शरीर को फायदे भी मिलते हैं। लेकिन गलत तरीके से इसका सेवन करना सेहत के लिए गंभीर होता है। चाय का सेवन करने वाले कुछ लोग इसमें नमक मिलाकर भी पीते हैं। नमक वाली चाय सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है।

नमक वाली चाय पीने के नुकसान

नमकीन चाय एक प्रकार की चाय है जिसमें नमक और अन्य मसाले डाले जाते हैं। अक्सर लोग चाय बनाते समय दूध के साथ कुछ मात्रा में नमक भी डाल देते हैं। सर्दी-जुकाम या इन्फेक्शन होने पर भी लोग नमकीन चाय का सेवन करते हैं। क्लीनिकल डाइटिशियन कहते हैं, चाय में दूध के साथ नमक मिलाकर पीना नुकसानदायक होता है। नमक वाली चाय का सेवन करने से कई गंभीर नुकसान का खतरा रहता है। इसलिए चाय में दूध के साथ नमक मिलाकर पीने से बचना चाहिए। नमक वाली चाय पीने के नुकसान इस तरह से हैं-

हाई ब्लड प्रेशर - दूध वाली चाय में नमक डालकर पीने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। नमक ज्यादा खाने से ब्लड में नाट्रियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बीपी बढ़ सकता है।

शरीर में पानी भरना - नमक वाली चाय का ज्यादा सेवन करने से शरीर में पानी भर सकता है। इसकी वजह से पेशाब की समस्या भी हो सकती है।

गैस और एसिडिटी - नमक के अधिक सेवन से पाचन तंत्र में समस्याएं हो सकती हैं, जिससे गैस और एसिडिटी का खतरा रहता है। यह पेट मे असहजता और तकलीफ का कारण बन सकता है।

पाचन तंत्र के लिए हानिकारक - नमकीन चाय का अधिक सेवन करने से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

शरीर में पानी की कमी - नमक के अत्यधिक सेवन से शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

नुकसान से कैसे बचें?

नमक वाली चाय का सेवन शरीर मे ऊपर बताई गई समस्याओं का कारण हो सकता है। इसके अलावा चाय का भी ज्यादा मात्रा मे सेवन करने से कई गंभीर नुकसान होने का खतरा रहता है। चाय पीने की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। इसके नुकसान से बचने के लिए डाइट में फल, सब्जी और हेल्दी चीजों को शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम और एक्सरसाइज का अभ्यास करने से भी इसके नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।

मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएँ

महिलाओं में तेजी से बढ़ती एक सामान्य स्वास्थ्य चिंता

मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएँ आज महिलाओं में तेजी से बढ़ती एक सामान्य स्वास्थ्य चिंता बनती जा रही हैं, जो उनके दैनिक जीवन और कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। इन्हीं समस्याओं में एक प्रमुख स्थिति है प्रीमेंस्ट्रुअलसिंड्रोम, जिसे एक दीर्घकालिक और चक्रीय विकार माना जाता है। यह समस्या आमतौर पर मासिक धर्म शुरू होने से 5 से 7 दिन पहले दिखाई देती है और इसका संबंध प्रजनन आयु में होने वाले स्टेरॉय डल हार्मोनों के उतार-चढ़ाव से माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पीएमएस का मुख्य कारण सामान्य हार्मोनल परिवर्तनों के प्रति शरीर की असामान्य संवेदनशीलता और अत्यधिक प्रतक्रिया हो सकता है।

आंकड़ों के अनुसार, विश्वभर में लगभग 40 मिलियन महिलाएँ पीएमएस से प्रभावित हैं, जबकि भारत में इसकी व्यापकता 61.7% से 72.3% के बीच बताई जाती है, जो इसकी गंभीरता को दर्शाता है। इस समस्या से जुड़े 150 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें वजन बढ़ना, जोड़ों और मांस पेशियो में दर्द, मुंहासे, पीठदर्द, पेटफूलना, पेट में ऐंठन, ऊर्जा की कमी, भूख और प्यास में बदलाव, कब्ज, हृदयगति मे वृद्धि, दैनिक गतिविधियों में रुचिकी कमी, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन, तनाव, उदासी, थकान, स्तनों में संवेदनशीलता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई शामिल है। हालांकि PMS के लक्षणों को कम करने के लिए दवाइयाँ (फार्माकोलॉजिकल) और बिना दवा के उपायों (नॉन-फार्माकोलॉजिकल) दोनों का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब तक इसका कोई निश्चित इलाज उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में ऑटोजेनिकट्रेनिंग (Autogenic Training - AT) एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर रही है। यह एक रिलैक्सेशन तकनीक है, जिसे 1930 में शुल्ट्ज द्वारा विकसित किया गया था। इसमें छह

मासिक धर्म से पहले होने वाली समस्याओं का समाधानः पीएमएस और ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की भूमिका

विशेष वाक्यों की मानसिक पुनरावृत्ति के माध्यम से शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और धीमी वनियंत्रित श्वास को अपनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटो जेनिक ट्रेनिंग से मानसिक शांति और गहरी विश्राम अवस्था प्राप्त होती है, जिससे शरीर के सिम्पेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक तंत्र के बीच संतुलन स्थापित होता है। यह प्रक्रिया दर्द को कम करने में भी सहायक होती है, क्योंकि इससे ऊतकों की ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, लैक्टिकएसिड का अपघटन होता है, मांसपेशियों का तनाव और चिंता घटती है, और शरीर में एंडोर्फिन जैसे प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन का स्राव बढ़ता है। इस प्रकार, PMS जैसी समस्या के प्रबंधन में जागरूकता और रिलैक्सेशन तकनीकों का अपनाना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

- **डॉ शालिनी (पीटी)**, सहायक प्रोफेसर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
- **डॉ. दिव्या खाती (पीटी)**, सहायक प्रोफेसर, रयात बाहरा विश्वविद्यालय, मोहाली
- **और डॉ. श्वेता वर्मा (पीटी)**, सहायक प्रोफेसर, रयात बाहरा विश्वविद्यालय, मोहाली

विधायक निधि के ऑनलाइन संचालन के लिए संभाग स्तरीय दिया गया प्रशिक्षण

विधायक निधि के कार्य अब ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से होंगे संचालित

दुर्ग/ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडीएस) की संपूर्ण प्रक्रिया को 01 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने के लिए दुर्ग संभाग के सभी जिलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय (साइंस कॉलेज) के राधाकृष्णन हॉल में दिया गया। संचालनालय योजना एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त संचालक श्री डी.एस.वर्मा एवं श्री संतोष राय ने विधायक निधि की पारदर्शी डिजिटल रूपरेखा की विस्तार से जानकारी दी।

इस दौरान कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने कहा कि सांसद निधि के कार्यों के लिए ई-साक्षी पोर्टल का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अनुशंसा प्राप्त करना, स्वीकृति जारी करना और आदेश करना जैसे कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब विधायक निधि के कार्यों को भी इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष से रायपुर में इस प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था और अब इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि नई प्रणाली लागू होने पर प्रारंभ में अनेक प्रकार की शंकाएं होती है, लेकिन ये बदलाव प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किए जाते हैं। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन का उदाहरण देते हुए बताया कि इससे सभी विभागों में कार्यप्रणाली में तेजी और सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि की स्वीकृति और राशि जारी करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रक्रिया को बारीकी से समझने को कहा, ताकि प्रणाली का क्रियान्वयन प्रभावी और सुचारू रूप से किया जा सके।

प्रशिक्षण में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय की उप संचालक श्रीमती कविता एन्थोनी, सहायक संचालक श्री सागर साहू, सहायक सांख्यिकी अधिकारी रायपुर श्रीमती सावित्री साहू और विधायक निधि शाखा के कर्मचारी, विधायकों के निज सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नगर निगम, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी-कर्मचारी सहित दुर्ग संभाग के अंतर्गत समस्त जिले-दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान एवं मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के प्रतिभागी शामिल हुए।

स्वास्थ्य अमला पीलिया से प्रभावित क्षेत्र का किया भ्रमण

दुर्ग,/ वार्ड-67 सेक्टर 7 पश्चिम सड़क 37 ए भिलाई नगर में पीलिया के मरीजों की जानकारी होने पर 10 अप्रैल 2026 को डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के निर्देशन में एवं डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्वेलेंस अधिकारी, दुर्ग के मार्गदर्शन में डॉ. पियाम सिंग, प्रभारी अधिकारी, सिविल हॉस्पिटल सुपेला भिलाई व श्रीमती रितीका सोनवानी, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट, दुर्ग श्री विजय सेजुले, सुपरवाईजर, श्री हितेन्द्र कोसरे, बीईटीओ एवं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के साथ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दानी से प्राप्त जानकारी अनुसार आज प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 110 घरों का भ्रमण कर 11 पीलिया से ग्रसित नए मरीज पहचान किये व अन्य लक्षणयुक्त 07 व्यक्तियों का ब्लड सैंपल जाँच हेतु हमर लैब जिला चिकित्सालय भेजा गया। इस प्रकार उक्त संक्रमित क्षेत्र में आज दिनांक तक कुल 15 पीलिया के मरीज़ मिले, जिनमें से 2 नये मरीज भर्ती हुए तथा 2 पुराने मरीज डिस्चार्ज हुए इस प्रकार कुल भर्ती 4 मरीज श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईस, भिलाई में उपचाररत है। प्रभावित क्षेत्र के तीन घरों से पीने के पानी का सैंपल जाँच हेतु चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कचांदुर भेजा गया है, भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा पानी टैंकर की व्यवस्था संक्रमित क्षेत्र में की गई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के पीएचई विभाग द्वारा पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। अतएव आम जनता के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया जिसमें जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग, दुर्ग आम जनता से अपील करता है। पीलिया हेतु पीलिया प्रदूषित जल व भोजन से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो विषाणुओं के संक्रमण से होता है। विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों के भीतर बीमारी के लक्षण प्रकट होते है। पीलिया के प्रमुख लक्षण भूख न लगना, पीले रंग की पेशाब होना, भोजन का स्वाद न आना, उल्टी लगना या होना, सिर में दर्द होना एवं कमजोरी तथा थकावट का अनुभव करना, पेट के दाहिने तरफ ऊपर की ओर दर्द होना, आंखे व त्वचा का रंग पीला होना।

दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर दिल्ली जाएगा प्रतिनिधिमंडल : रतिराम कोसमा

दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए लंबे समय से चल रहे प्रयासों के बाद शहर वासियों को बार-बार यह बताया जा रहा था की इसी शिक्षा सत्र से दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय आरंभ हो जाएगा। इस हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा अस्थाई भवन के रूप में बीएसपी प्राथमिक शाला क्रमांक 6 जिसमें वर्तमान में आदिवासी बच्चों का हॉस्टल चल रहा है को बंद कर कर अस्थाई रूप से केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात कही गई। बीएसपी प्रबंधन ने उसे भवन को अस्थाई रूप से उपयोग करने के लिए अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। जून- जुलाई 2025 में ही यह घोषणा भी कर दिया गया था की आगामी शिक्षा सत्र में दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय आरंभ हो जाएगा। इस शिक्षा सत्र के प्रारंभ में दल्ली राजहरा के केंद्रीय कर्मचारियों ने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जब केंद्रीय विद्यालय का पोर्टल खोला तो वही ढाक के तीन पात मिले। लगातार प्रयासों के बाद भी एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय की सूची में दल्ली राजहरा का कहीं पर भी नाम नहीं आया था। स्पष्ट है कि जिन लोग सिर्फ घोषणा कर रहे थे उन लोगों ने ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किया केंद्रीय विद्यालय को समय पर दल्ली राजहरा में खोले जाने के लिए। उपरोक्त बातों को दल्ली राजहरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि रतिराम कोसमा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही। विज्ञप्ति में आगे बताया कि क्षेत्रिय विधायक अनिला भेड़िया के निर्देश पर राज्यसभा सांसद फूलों देवी नेताम से इस संबंध में एक दौर की चर्चा हो चुकी है और उन्होंने दल्ली राजहरा में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु दिल्ली स्तर पर अपने प्रयास का आश्वासन दिया है। रतिराम कोसमा ने आगे बताया कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 9 अप्रैल को राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम से मिलकर केंद्रीय विद्यालय के संबंध में विस्तार से जानकारी सांसद को देंगे और दिल्ली स्तर पर केंद्रीय विद्यालय आगामी शिक्षण सत्र में दल्ली राजहरा में आरंभ किए जाने हेतु निरंतर प्रयास करने की दिशा में काम करेंगे।

ठेकेदारों द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती तो सख्त कार्रवाई की जाए

मुख्य अभियंता ने बेमेतरा जिले की सड़कों का किया सघन निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

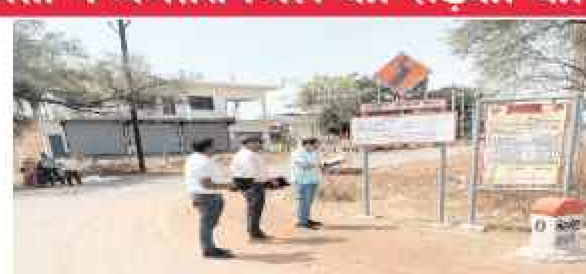

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन्स रायपुर के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा द्वारा बेमेतरा जिले का दौरा कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण 03 अप्रैल 2026 को किया गया, जिसमें विशेष रूप से 05 वर्ष की संधारण अवधि (मेंटेनेंस पीरियड) वाले सड़कों की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सड़कों की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं वर्तमान हालत का सूक्ष्म मूल्यांकन किया गया। मुख्य अभियंता ने जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर सड़कों के रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कुछ स्थानों पर नियमित संधारण कार्यों में कमी देखी जा रही है, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का नियमित रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ठेकेदारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता ने सड़कों के संधारण से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे पैच रिपेयर, पॉट होल्स (गड्ढों) की मरम्मत, सड़क किनारे उगी झाड़ियों की सफाई, पुल-पुलियों की रंगाई-पुताई तथा आवश्यक मरम्मत कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण संधारण से ही सड़कों की दीर्घायु सुनिश्चित की जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बना रह सकता है।

मुख्य अभियंता शर्मा ने यह भी निर्देशित किया कि जिन ठेकेदारों द्वारा 05 वर्ष की नियमित संधारण अवधि के दौरान कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में संबंधित ठेकेदारों की बैंक गारंटी राशि राजसात (जब्त) करते हुए डी.एल.पी. (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया गया है। इससे कार्य में जवाबदेही एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता मुकेश कुमार साकरकर, सहायक अभियंता अमर सिंह पैकरा एवं उप अभियंता यशवंत कुमार साहू सहित विभागीय अधिकारी एवं तकनीकी अमला उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सतत मॉनिटरिंग एवं समयबद्ध संधारण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कुसुमकसा रेलवे ब्रिज के पास एक बड़ा हादसा होते टला

बल्लीराजहरा। कुसुमकसा रेलवे ब्रिज के पास आज एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब पायल कंपनी की एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 9 अप्रैल लगभग दोपहर 3:30 बजे की है। बस बालोद से दल्ली राजहरा की ओर आ रही थी, तभी कुसुमकसा रेलवे ब्रिज के समीप चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया और बस अनियंत्रित होकर ढलान की ओर नीचे जा उतरी। घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा फरार चालक की तलाश की जा रही है तथा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।स्थानीय लोगों के अनुसार, बस की रफ्तार अधिक नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा गंभीर जनहानि हो सकती थी।

कच्चे छप्पर से पक्के मकान तक—बिहारी का बदला जीवन

बेमेतरा। जिले के साजा जनपद अंतर्गत ग्राम केहका निवासी बिहारी पिता दुखित की जीवन यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन चुकी है। कुछ वर्ष पहले तक उनका परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहा था, जहाँ हर दिन संघर्ष और असुरक्षा का सामना करना पड़ता था। मिट्टी की दीवारें और खपरैल की छत मानसून के मौसम में बड़ी परेशानी का कारण बनती थीं, जिससे पूरा परिवार भय और असुविधा में जीने को मजबूर था। बरसात के दिनों में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते थे। छत से टपकता पानी, दीवारों में सीलन और रातभर जागकर समय बिताना बिहारी के परिवार की मजबूरी बन चुकी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे स्वयं पक्का मकान बनवाने में असमर्थ थे, जिससे उनका अपने घर का सपना अधूरा ही नजर आता था। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई। योजना के तहत उनका चयन हुआ और शासन से प्राप्त आर्थिक सहायता ने उनके सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। बिहारी बताते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उन्हें पक्का मकान मिल पाएगा। सरकारी सहयोग ने उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता को समाप्त कर दिया। योजना के तहत प्राप्त किस्तों का सही उपयोग करते हुए बिहारी ने मेहनत और लगन से अपने पुराने कच्चे घर की जगह एक मजबूत और सुंदर पक्का मकान तैयार कर लिया। अब उनका परिवार सुरक्षित वातावरण में जीवन बिता रहा है। पक्के घर के निर्माण से न केवल उन्हें मौसम की मार से राहत मिली है, बल्कि बार-बार मरम्मत के खर्च से भी छुटकारा मिल गया है।

बिहारी पिता दुखित अपने नए घर में ससम्मान जीवन जी रहे हैं। इस बदलाव ने उनके जीवन स्तर को नई दिशा दी है। ग्राम पंचायत केहका और जनपद पंचायत साजा के अधिकारियों के सहयोग तथा शासन की इस जनकल्याणकारी योजना ने उनके जैसे अनेक ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का संचार किया है।

जुआ खेलते 03 जुआडियों से 26,500 रूपये जब्त

बेमेतरा। चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद एवं चौकी देवकर पुलिस टीम द्वारा जरिए मुखबिर सुचना पर बेलाही खार ग्राम सहसपुर में रेड कार्यवाही कर 03 जुआड़ी से नगदी रकम 26,500/- रूपये, एक मोटर सायकल कीमती 35,000/- रूपये, कुल जुमला 61,500/-रूपए एवं 52 पत्ती तास को जप्त किया गया। चौकी देवकर पुलिस टीम को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सहसपुर के बेलाही खार आम जगह में कुछ लोग टार्च की रोशनी में बैठकर 52 पत्ती तास से रूपये पैसे का दांव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे है कि सुचना पर चौकी देवकर पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुच कर सुचना के अधार पर रेड कार्यवाही किया गया, रेड कार्यवाही के दौरान कुछ लोग पुलिस को आते देखकर भाग निकले मौके पर 03 जुआड़ी पकड़े गए। जिसमें चौकी देवकर थाना साजा में 01 प्रकरण दर्ज कर 03 जुआडियानो टेकराम साहू उम्र 41 वर्ष, निवासी राजपुर थाना धमधा जिला दुर्ग, आशाराम साहू उम्र 35 वर्ष, निवासी सहसपुर चौकी देवकर थाना साजा, जिला बेमेतरा, भोजराम साहू उम्र 26 वर्ष, निवासी राजपुर थाना धमधा जिला दुर्ग के विरूद्ध धारा 3(2),छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत कार्यावाही की गई है। जुआडियों के पास एवं फड़ से कुल जुमला नगदी रकम 26,500/- रूपये, एक मोटर सायकल क्रमांक सीजी 09 जेजी 8581 कीमती 35,000/- रूपए, कुल जुमला 61,500/-रूपए एवं 52 पत्ती तास जप्त को जप्त किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक अलील चंद, प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र तिवारी, आरक्षक मोहित देवांगन, भूषण मारकंडेय, मुकेश पाल, दीपक राजपूत, हुंकार दास टंडन, मुकेश राजपूत सहित अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण योगदान रहा।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को लेकर जिला स्तर पर कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश

10 मार्च 2024 से शुरू अभियान, 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य

दुर्ग,/ जिले में बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम के उद्देश्य से संचालित बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत राज्य शासन ने सभी जिलों को जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान 10 मार्च 2024 से शुरू किया गया है और चरणबद्ध रूप से वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनमें ग्राम पंचायत सचिव, सेक्टर पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह पंजी का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि सभी विवाहों का पूर्व पंजीयन हो सके और बाल विवाह की जानकारी समय रहते प्राप्त की जा सके। साथ ही, जिन क्षेत्रों या समुदायों में बाल विवाह की घटनाएं अधिक होती रही हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ कानून अपराध भी है। इसमें शामिल वर-वधू के अभिभावकों, रिश्तेदारों और विवाह कराने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनप्रतिनिधियों, पंचायत एवं नगरीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों और आम जनता से इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की है। कलेक्टर श्री सिंह ने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आगामी 26 मार्च 2026 को रामनवमी एवं 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी सजगता के साथ कार्य करते हुए संभावित बाल विवाह की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित विभागों के मैदानी अमले को सक्रिय कर व्यापक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम के लिए तैयार की गई जिला स्तरीय कार्ययोजना को समय-सीमा में महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जल संरक्षण पर जोर, ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के तहत कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश

दुर्ग/ जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

बैठक में -मोर गांव मोर पानी- महाअभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि वर्षा की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के उद्देश्य से जल संग्रहण आधारित कार्यों को अधिक से अधिक स्वीकृत कर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वप्रेरणा से सोकपिट का निर्माण कराया जाए। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कम लागत एवं प्रभावी परिणाम देने वाले सोकपिट एवं जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता से चयनित कर समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि मनरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्यों का चयन मांग आधारित हो तथा श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार योजना अंतर्गत कार्यरत सभी श्रमिकों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए उसका समयबद्ध अपलोड सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों की जियो-टैगिंग में तेजी लाने, लंबित प्रस्तावों को नियमानुसार प्रस्तुत कर शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सामाजिक अंकेक्षण अंतर्गत लंबित निकासी बैठकों को शीघ्र आयोजित कर एटीआर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। जानकारी अनुसार जिला दुर्ग में 50, जनपद पंचायत पाटन में 16 एवं जनपद पंचायत धमधा में 55 निकासी बैठकें लंबित हैं, जिन्हें तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में गति लाने तथा मनरेगा के माध्यम से हितग्राहियों को 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com